नई दिल्ली
सोमवार
02 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 59
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



अंतिम टी-20 में न्यूजीलैंड की सात विकेट से जीत,...पेज-06

DELHIN/2014/58158

मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड के कमांड सेंटर का...पेज-05

एक नजर

आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, गाजियाबाद की डासना जेल भेजे गए

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गाजियाबाद की विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने उन्हें अदालत में पेश किया था। इस दौरान पत्रकारों ने जब आजम खान से पूछा कि क्या वह इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने निराशा और बेबसी भरे अंदाज में कहा, ''अब क्या है, बोलने के लिए।'' इस बीच सपा के कई नेता भी अदालत परिसर पहुंचे। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शनिवार शाम रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया था। रविवार को उन्हें पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं तथा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है। ईडी विश्वविद्यालय की करोड़ों रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुकी है। एजेंसी इस मामले में पूछताछ के लिए आजम खान की कस्टडी रिमांड मांग रही थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। इस घटनाक्रम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

राहुल और इंडी गठबंधन की असलियत देश देख रहा हैः रेखा गुप्ता

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का मंच सजाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की असलियत देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर की तारीख देश भूला नहीं है। 1984 में इसी दिन दिल्ली की सड़कों पर सिखों के नरसंहार का भयावह अध्याय लिखा जा रहा था। हजारों निर्दोष सिख परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं और आज उसी तारीख को कांग्रेस रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाने का ढोंग कर रही है। यह राजनीतिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री ने रविवार को हरिनगर से तिलक नगर तक भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा के दौरान यह बाते कहीं।उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में जब दिल्ली के व्यापारी, छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले अपने परिवारों की खुशहाली के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तब कांग्रेस अपनी राजनीतिक नौटंकी से दिल्ली की रफ्तार रोकने और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने पर तुली है। उन्होंने कहा कि पहले झूठ फैलाओ, फिर जनादेश को बदनाम करो, सड़कों पर अराजकता का माहौल बनाओ और अपनी राजनीतिक हताशा की कीमत देश और दिल्ली की जनता से वसूलो। यही राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देकर 1984 का कलंक नहीं मिटा सकती। न ही जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने की हताशा में दिल्ली के व्यापारियों की रोजी-रोटी को दांव पर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी याद रखें, जनादेश से मिली हार का बदला देश से और अपनी राजनीतिक नाकामी की कीमत दिल्लीवालों से नहीं वसूली जा सकती।

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली, राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने कहा-ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना है



नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था और उसमें मतदाताओं के नाम काटे गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहला कदम ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना है।

रैली से पहले विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक मार्च निकाला। मार्च में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खुले वाहन में सवार होकर पहुंचे नेताओं का रामलीला मैदान में स्वागत किया गया। इसके बाद मंच से विपक्षी नेताओं ने सभा को संबोधित किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की नेहा बोरा ने भी मंच से संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती के संबोधन के बाद राहुल गांधी ने मंच संभाला। राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटेंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यह सामान्य चोरी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के वोट और उसकी आवाज की चोरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे लेकिन उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। विपक्ष हिंसा और नफरत में विश्वास नहीं करता, उसका उद्देश्य देश में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की आवाज विपक्ष के लिए जरूरी है। यह विरोध प्रदर्शन देश के लोकतंत्र को बचाने की आवाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। इसका असर किसानों, युवाओं और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और 18 घंटे पढ़ाई करने वाले छात्र को शिक्षा और रोजगार के रूप में उसका परिणाम मिलना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

खरगे ने दावा किया कि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में जनता ने सरकारें नहीं चुनीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके सरकारें बनाई गईं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है। खरगे ने कार्यकर्ताओं से संघर्ष जारी रखने की अपील की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रामलीला मैदान आज लोकतंत्र की हल्दीघाटी बन गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग वहां आए थे, उन्हें अब बाहर जाना पड़ेगा। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में भाजपा और उसके सहयोगियों की ऐसी विदाई होगी कि वे दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आमतौर पर रामलीला मैदान में रामायण का मंचन होता है लेकिन आज यहां वोट चोरी के खिलाफ महाभारत हो रहा है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रधानमंत्री की कठपुतली बताया। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यदि लोग नहीं जागे तो लोकतंत्र और संविधान कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि विपक्षी दलों और समर्थकों ने सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया है। रैली में विपक्ष की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या उन्हें पद से हटाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के स्थान पर बैलेट पेपर की वापसी की मांग उठाई गई।

राहुल गांधी पर भाजपा का हमला, लोकतंत्र के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की कर रहे साजिश

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में आज जो कुछ हो रहा है, वह लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं बल्कि लोकतंत्र के नाम पर देश को अराजकता में धकेलने की सोची-समझी साजिश है। नड्डा ने रविवार को एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि यह उन लोगों का सुनियोजित नाटक है, जिन्हें जनता बार-बार नकार चुकी है। जनता इस सच्चाई को अच्छी तरह समझती है। राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पहली कड़ी, झूठ और अफवाह फैलाना है। दूसरी कड़ी सड़कों पर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करना, तीसरी कड़ी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और चौथी कड़ी विदेशी ताकतों के इशारे पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र की आड़ में ऐसा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश की शांति, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नवंबर के काले इतिहास को नहीं छिपा सकते और न ही दिल्ली के व्यापारियों के आँसुओं का हिसाब देने से बच सकते हैं। भारत एक सशक्त लोकतंत्र है, जो आपकी 'दंगा आधारित राजनीति' से नहीं बल्कि संविधान और जनता के जनादेश से चलेगा। उन्होंने कहा कि यह रैली कांग्रेस के राजनीतिक

हवाई ईंधन और 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, नई दरें पूरे देश में लागू

हवाई सफर और रेस्त्रां का खाना हो सकता है महंगा

नई दिल्ली,एजेंसी। त्योहारी सीजन के बीच आम जनता और हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में आई मजबूती को देखते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी हवाई ईंधन और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।



हर महीने की पहली तारीख को होने वाली इस समीक्षा के तहत 1 नवंबर से नई दरें पूरे देश में लागू कर दी गई हैं, जिससे इस दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले लोगों के बजट पर भी असर पड़ सकता है तेल कंपनियों के अनुसार एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में 1.37 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एटीएफ का भाव 137.12 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 138.50 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। हवाई ईंधन की कीमत में यह लगातार चौथे महीने वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विमानन कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। एविएशन सेक्टर के जानकारों का कहना है कि किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेशनल कॉस्ट में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक होती है।

चक्रवाती तूफान 'मुरासु' हुआ सक्रिय, आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान 'मुरासु' में तब्दील हो गया है। आज सुबह 11:30 बजे यह तूफान दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 2 नवंबर की सुबह तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसके 2 नवंबर की आधी रात 11:30 बजे से 3 नवंबर की सुबह 4 बजे के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

बदलती हुई वायु सेना को हमेशा लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिएः आशुतोष दीक्षित

एयर चीफ मार्शल को रेसकोर्स एयर फोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

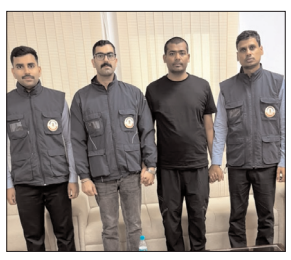
नई दिल्ली,एजेंसी। नए वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने रविवार को 29वें एयर चीफ के तौर पर चार्ज संभाल लिया। इसके पहले उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित किया। वहां मौजूद अपनी मां और सास के पैर छुए और फिर उन्हें सैल्यूट किया। एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को रेसकोर्स एयर फोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बतौर एयर चीफ उन्होंने पहले ही संबोधन में कहा कि अगले दशक में भारत को जिस फोर्स की जरूरत होगी, उसमें बदलती हुई वायु सेना को हमेशा लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए।



एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित इलेक्ट्रिक गाड़ी (ईवी) में चार्ज लेने पहुंचे। सस्टेनेबल मोबिलिटी के भविष्य को अपनाते हुए एयर चीफ मार्शल ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ी अपना ली है। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि 'मैं 29वें एयर चीफ के तौर पर इंडियन एयर फोर्स की कमान संभाल कर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का दिखाए गए भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया। आज सुबह उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी, मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उनकी हिम्मत ही वह पैमाना है, जिससे हम खुद को मापेंगे। रेसकोर्स एयर फोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने कहा कि 'मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जगह ले रहा हूं, जिनके नेतृत्व में 'ऑपरेशन सिंदूर' में एयर फोर्स ने दिखाया कि सटीक और निर्णायक एयर पावर क्या हासिल कर सकती है। मैं उन्हें एक ऐसी फोर्स सौंपने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो पूरी तरह तैयार है।

महादेव एप सट्टेबाजी मामले का मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर ओमान से भारत लाया गया

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महादेव एप के जरिए अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट चलाने के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर का ओमान से प्रत्यर्पण करा लिया है। सीबीआई की विशेष टीम उसे भारत लेकर पहुंची है। उसे सोमवार को रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चंद्राकर सीबीआई के दो मामलों में वांछित है, जिनमें आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में भी उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।



सीबीआई के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मामलों की जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ली थी। जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। यह क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी कराता था। इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी आधारित पैनल और शाखाओं का नेटवर्क बनाया गया था, जिसके जरिए लोगों को जोड़ा जाता था और उनसे सट्टे की रकम जमा कराई जाती थी। जांच में पता चला कि सट्टेबाजी से हासिल रकम को बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों के जरिए भेजा जाता था। कई लेनदेन के माध्यम से रकम की परतें बनाई जाती थीं और हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि इस रकम का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण राशि देने में इस्तेमाल किया गया, ताकि सिंडिकेट बिना किसी बाधा के काम कर सके। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी तथा जालसाजी से जुड़े प्रावधानों के अलावा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बेंगलुरु में बन रही है

280 किमी/घंटा होगी अधिकतम रफ्तार

बेंगलुरु,एजेंसी। भारत उच्च गति रेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली पूर्णतः स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण को तेजी से बढ़ा रहा है जो अगले वर्ष 15 अगस्त को वापी से सूरत के बीच चलाई जाएगी। इस हाई-स्पीड ट्रेन का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित बीईएमएल संयंत्र में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बीईएमएल के 'आदित्य' संयंत्र में स्वदेशी बुलेट-ट्रेन बी28 के निर्माण का जायजा लिया।



रेल मंत्री ने कारबॉडी फैब्रिकेशन (डिब्बे के निर्माण) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च-सटीकता वाले जिग्स और फिक्स्चर सहित विशेष विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। उन्होंने अंडरफ्रेम, साइडवॉल, छत की असेंबली, कार असेंबली, सतह की तैयारी (ह्यह्वह्द्धड्डष्ट्र श्वह्द्दश्वड्डह्वड्डह्लद्धश्ठ्ठ) और ट्रीटमेंट जैसे उत्पादन के प्रमुख चरणों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। हाई-स्पीड रेल परिचालन के लिए आवश्यक सटीकता, मजबूती और गुणवत्ता मानकों को हासिल करने में ये आधुनिक निर्माण प्रक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 'स्क्वीज टेस्ट' का प्रदर्शन भी देखा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुणवत्ता जांच प्रक्रिया है, जिसमें ट्रेन की कारबॉडी की संरचनात्मक मजबूती, कठोरता और उसके आकार की स्थिरता का आकलन करने के लिए उस पर नियंत्रित दबाव और खिंचाव डाला जाता है।

उन्होंने हाई-स्पीड यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलने वाले आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्री सीटों का अवलोकन किया। इसके अलावा, उन्होंने ऑनबोर्ड प्रणालियों और उपकरणों, जैसे—हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कपलर और अन्य ट्रेन उपकरणों एवं असेंबली का गहन मुआयना किया। रेल मंत्री ने साइड मॉड्यूल और रूफ (छत) मॉड्यूल के निर्माण के साथ-साथ उनके इंटीग्रेशन (एकत्रीकरण) और असेंबली कार्यों का भी जायजा लिया। रेल मंत्रालय के अनुसार, स्वदेशी विशेषज्ञता से निर्मित यह बुलेट ट्रेन भारतीय परिस्थितियों और यात्रियों की सुरक्षा तथा आराम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन की अधिकतम टेस्ट स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा तथा परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। 202 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 8 कोच (4 मोटर कार और 4 ट्रेलर कार) शामिल हैं।

दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक विकसित होगा आधुनिक कॉरिडोर : रेखा गुप्ता

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार



नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी के नेताजी सुभाष मार्ग को नए स्वरूप में विकसित करने की योजना तैयार कर रही है। इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की इस पुनर्विकास परियोजना में दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक (करीब 3.3 किलोमीटर) आधुनिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। योजना में सड़क के सौंदर्यीकरण के साथ आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को भी एक-दूसरे से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री व इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने रविवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए यह मार्ग आवागमन के साधन के साथ-साथ दिल्ली के इतिहास, विरासत, स्थापत्य, संस्कृति और आधुनिक शहरी जीवन के बीच एक जीवंत सेतु के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली गेट से शुरू होकर कश्मीरी गेट तक जाएगा। सौंदर्यीकरण को सड़क की उपलब्ध चौड़ाई के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हिस्से में कश्मीरी गेट से जीपीओ चौक तक रखा गया है। यह इस कॉरिडोर की सबसे व्यस्त सड़क है और इसकी चौड़ाई 12 से 24 मीटर है। दूसरे हिस्से में जीपीओ से ब्रिज मोहन चौक (जामा मस्जिद की ओर जाने वाला चौराहा) की सड़क को रखा गया है। इसकी औसत चौड़ाई 45 मीटर है। तीसरे हिस्से में ब्रिज मोहन चौक से दिल्ली गेट चौराहे की सड़क रखी गई है। इसकी औसत चौड़ाई 16.8 से 26 मीटर है। इस कॉरिडोर के इन तीनों हिस्सों में सड़क की चौड़ाई व अन्य उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए। यातायात के साथ पैदल और गैर-मोटर चालित परिवहन को भी पर्याप्त स्थान देने की व्यवस्था की गई है। इनमें फुटपाथ, बस लेन और मोटर वाहन लेन के अलावा पार्किंग व्यवस्था, पैदल प्लाजा, साइकिल ट्रैक आदि शामिल है। इसके अलावा इस सड़क के दोनों ओर आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा और बस स्टॉप्स को अपग्रेड किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं का आधार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से मौजूदा स्ट्रीटस्केप परियोजना के लिए साझा किए गए डिजाइन दिशा-निर्देश शामिल हैं।

परियोजना की प्रमुख विशेषता नेताजी सुभाष मार्ग के आसपास मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक महत्व के स्थलों को एक समग्र स्वरूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत लाल किला, जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च, कश्मीरी गेट का क्षेत्र, लालकिला से जुड़ा चांदनी चौक का चौराहा, सुभाष पार्क, हिंदी पार्क, आईजीटी यूनिवर्सिटी, अग्रसेन पार्क, सुनहरी मस्जिद जैसे प्रमुख स्थलों को कॉरिडोर की योजना में शामिल किया गया है। साथ ही अग्रसेन पार्क, लोथियान कब्रिस्तान, पुराना रेलवे स्टेशन चौक, लाल किला ग्रीन पॉकेट, लाल किले का दशहरा मेला स्थल, चांदनी चौक-लालकिला चौक, सुनहरी मस्जिद बाग, सुभाष पार्क, ब्रिज मोहन चौक, दिल्ली गेट चौक, एकता स्थल और हिंदी पार्क सहित 12 प्रमुख स्थानों और हरित क्षेत्रों के एकीकरण का प्रस्ताव है। इससे मार्ग के आसपास उपलब्ध हरित स्थानों को बेहतर ढंग से विकसित करने और शहर के इस ऐतिहासिक हिस्से को अधिक आकर्षक बनाने की परिकल्पना की गई है। योजना में दिल्ली गेट के आसपास के क्षेत्र को विशेष रूप से विकसित करने का प्रस्ताव है। यहां विरासत परिचय उद्यान (हेरिटेज इंटरप्रिटेशन पार्क) विकसित करने की परिकल्पना की गई है। यहां प्रतिमा, आकर्षक मंडप (पैवेलियन), हरित क्षेत्र, पैदल आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। पार्क के डिजाइन में हरियाली, सजावटी पौधों, वृक्षों और विरासत से जुड़े स्थापत्य तत्वों को प्रमुखता दी गई है। सुभाष मार्ग के सौंदर्यीकरण के प्रस्तावित सौंदर्यीकरण में सड़क के दोनों ओर पेड़-पौधे, फूलों की क्यारियां, हरित डिवाइडर और आकर्षक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा सजावटी दीवारें, बैठने के लिए व्यवस्थित स्थान तथा विरासत की पहचान दर्शाने वाले डिजाइन शामिल किए गए हैं। सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए निर्धारित क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल और सुव्यवस्थित जंक्शन भी बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास, गौरवशाली विरासत, विविध संस्कृति और जीवंत परंपराओं की पहचान भी है। पुरानी दिल्ली का क्षेत्र इस ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, सुभाष पार्क और कश्मीरी गेट जैसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल हमारी समृद्ध विरासत की कहानी कहते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष मार्ग का पुनर्विकास इसी ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए राजधानी को आधुनिक शहरी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विकास के नाम पर दिल्ली की ऐतिहासिक आत्मा और सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता न हो, बल्कि आधुनिक सुविधाएं उसकी विरासत को और अधिक गौरव एवं गरिमा प्रदान करें।

सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के समर्थन में भाजपा का मार्च, केंद्रीय मंत्री ने कहा- 42 साल बाद भी त्रासदी को नहीं भुला पाया है सिख समुदाय

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सिख विरोधी हिंसा में एकतरफा तरीके से हजारों लोगों की हत्या की गई, इसे नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 42 साल बाद भी सिख समुदाय उस त्रासदी को पूरी तरह भुला नहीं पाया है। वे रविवार को हरि नगर में आयोजित मार्च में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज दिल्ली के हरि नगर में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के समर्थन में मार्च निकाला। इसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, मंत्री आशीष सूद, सरदार अरविंदर सिंह लवली और बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान भाजपा नेताओं ने 1984 की हिंसा के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और घटना की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1984 में दिल्ली में 2,733 और देशभर में करीब 3,325 लोगों की हत्या हुई थी। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि सिख समाज इन्हें अधूरा मानता रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय हमलावर मतदाता सूची देखकर सिख परिवारों के घरों तक नहीं पहुंच रहे थे बल्कि उन्हें पहले से लोगों की पहचान और उनके घरों की जानकारी दी जा रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे तैयारी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पीड़ितों के दर्द को स्वीकार करने और पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी कार्यक्रम के लिए दूसरी तारीख चुनी जा सकती थी तो 1 नवंबर को ही आयोजन करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा दोबारा देश या दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज संविधान की प्रति लेकर चलने और लोकतंत्र की दुहाई देने वालों से सिख समाज पूछ रहा है कि नवंबर 1984 में जो हुआ, क्या वह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? हजारों परिवारों ने अपने परिजनों को खोया और अनेक माताएं, बहनें आज भी उस दर्द के साथ जी रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार 1984 की घटनाओं की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वर्ष 1975 के आपातकाल और 1984 की सिख विरोधी हिंसा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वालों को पहले अपने अतीत का जवाब देना चाहिए।

मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने साल 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ ताजा जमानती वारंट जारी किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया।

आज सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे लेकिन अब वे भारत छोड़ चुके हैं। तब कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ ताजा जमानती वारंट जारी किया। इसके पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था। यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा में 2345 नए पद स्वीकृत

नई दिल्ली। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) में अलग-अलग श्रेणियों के 2,345 नए पद सृजित किए जाएंगे। वर्ष 1942 में विभाग की स्थापना के बाद 84 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर पदों का सृजन किया जा रहा है। इस फैसले के बाद विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा और लोगों की जान बचाने के लिए अग्निशमन सेवा को बढ़ती जरूरतों के अनुसार मजबूत बनाना जरूरी है। इसके तहत उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मंडल अधिकारी, सहायक मंडल अधिकारी, स्टेशन अधिकारी, उप अधिकारी, अग्रणी अग्निशामक, अग्नि ऑपरेटर, चपरासी, माली के पदों का विस्तार किया जाएगा। इससे विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर अग्निशमन और बचाव कार्यों में तैनात कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही विभागीय ढांचे को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन करने और आपात स्थितियों में कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राजधानी की तेजी से बढ़ती आबादी, विस्तारित शहरी क्षेत्र, घनी बस्तियां, बहुमंजिला इमारतें, औद्योगिक प्रतिष्ठान और जटिल बुनियादी ढांचा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। आग लगने या किसी अन्य आपदा की स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन, मजबूत नेतृत्व व्यवस्था और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता ही लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में अग्निशमन सेवा की भूमिका केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है। आग की घटनाओं के अलावा विभिन्न दुर्घटनाओं, आपातकालीन परिस्थितियों और बचाव अभियानों में भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में विभाग में पर्याप्त मानव संसाधन और प्रत्येक स्तर पर मजबूत कमान व्यवस्था होना आवश्यक है। विभाग में 2,345 अतिरिक्त पदों का सृजन केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय नहीं, बल्कि दिल्ली की जनसुरक्षा, संस्थागत क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं में किया गया महत्वपूर्ण निवेश है। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि लंबे समय से अपेक्षित इस कैडर पुनर्गठन से विभाग को अधिक मजबूत संस्थागत आधार मिलेगा और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। सार्वजनिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। शुरुआत में इसके पास केवल चार अग्निशमन केंद्र, 14 अग्निशमन वाहन व उपकरण और 186 कर्मचारी थे। वर्ष 1970 तक अग्निशमन केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

वासुदेव घाट पर मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ महापर्व की तैयारियों का लिया जायजा

नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ महापर्व के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वासुदेव घाट का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ घाट पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया तथा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ महापर्व से पहले सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा, घाटों की स्वच्छता, सुरक्षा और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर कपिल मिश्रा ने कहा कि छठ महापर्व दिल्ली की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि छठी मैया के भक्तों को पर्व के दौरान बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आपसी समन्वय के साथ तैयारियां समय पर पूरी करें ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और सुविधापूर्वक छठ महापर्व मना सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि छठ महापर्व का आयोजन श्रद्धा, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हो।

लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है, जब नागरिक जागरूक रहें : विजेंद्र गुप्ता

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे



नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है, जब नागरिक जागरूक रहें, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए। लोकतंत्र की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक की जागरूकता, सहभागिता और प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित सेक्टर-8 के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' जन-जागरूकता गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही।

इस गोष्ठी का आयोजन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व के प्रति जन-जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति नागरिकों के विश्वास और उनकी सक्रिय भागीदारी में निहित है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों के सम्मान तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के महत्व पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन की एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह जनता की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने और संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना, रचनात्मक जन-संवाद को प्रोत्साहित करना तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को अस्वीकार करना आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। इस गोष्ठी में दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही तथा निगम पार्षद रीता गोयल और स्मिता कौशिक सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं ने भी भाग लिया। गोष्ठी में लोकतांत्रिक जागरूकता, जनभागीदारी तथा भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों और संस्थाओं के संरक्षण में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया।

एमसीडी ने हेरिटेज यूनिटी वॉक और विद्यालयों में विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के शिक्षा विभाग ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साह और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया। इस अवसर पर कुतुब मीनार परिसर में विशेष हेरिटेज यूनिटी वॉक का आयोजन किया गया। वहीं, निगम के सभी विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। कुतुब मीनार परिसर में आयोजित हेरिटेज यूनिटी वॉक में एमसीडी के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों, स्टार पैरेंट्स, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सदस्यों, प्राथमिक शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज (इवनिंग) के एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में आयोजित इस पदयात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने का अवसर मिला। साथ ही, सरदार वल्लभभाई पटेल के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण, राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को सशक्त किया गया। इसी क्रम में एमसीडी के सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित प्रश्नोत्तरी, शपथ, पोस्टर निर्माण और परिचर्चा जैसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विरासत, संवैधानिक मूल्यों, आपसी सद्भाव और विविधता में एकता के महत्व से परिचित कराया गया। इस अवसर पर एमसीडी की निदेशक शिक्षा विभाग, आयुषी ने एमसीडी प्राथमिक विद्यालय, शेख सराय फेज-II तथा निगम श्री विद्यालय, जी-ब्लॉक, साकेत का दौरा कर विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों में सहभागिता की।

मंत्री कपिल मिश्रा गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में हुए शामिल



नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा शनिवार को आईजीआई स्टेडियम में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गायत्री परिवार के सभी साधकों, उपासकों और शिष्यों को नमन करते हुए मां गायत्री की चेतना, हवन, यज्ञ और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के प्रयासों की सराहना की। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस शताब्दी समारोह में उपस्थित सभी गायत्री परिवार के साधकों, उपासकों और शिष्यों को मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा परिवार वर्षों से गुरुदेव और माताजी से जुड़ा रहा। यहां तक कि मेरी बड़ी बहन का जन्म भी शांतिकुंज में हुआ है। गुरुदेव और परम पूजनीय माताजी के माध्यम से मां गायत्री की चेतना का प्रसार आज पूरे विश्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1962 से लेकर आज तक 80 से अधिक देशों और करोड़ों परिवारों तक मां गायत्री की चेतना पहुंचाने का पुण्य कार्य गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा है। शायद यही जीवन की सार्थकता है। आज जब पूरी दुनिया अनेक संकटों और चुनौतियों से जूझ रही है, तब आशा और प्रकाश का रास्ता ऐसे ही साधकों और उपासकों के माध्यम से निकलता है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस विश्व की कल्पना गुरुदेव और माताजी ने की थी, उसका निर्माण तभी संभव है, जब मां गायत्री की चेतना का प्रकाश पूरे विश्व तक पहुंचे। उन्होंने गायत्री परिवार के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की शक्ति, मां गायत्री की चेतना और हवन-यज्ञ की परंपरा से प्रत्येक परिवार को जोड़ने का कार्य अत्यंत सराहनीय है। मंत्री कपिल मिश्रा ने गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को शताब्दी समारोह की बधाई देते हुए उनके आध्यात्मिक और सामाजिक अभियान की निरंतर सफलता की कामना की।

एक नवंबर के काले दिन को देश कभी नहीं भूल सकता : सिरसा



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए निर्दोष सिखों की स्मृति और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दिल्ली में पदयात्रा निकाली गई। हरिनगर डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक आयोजित इस पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 01 नवंबर 1984 भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार में हजारों परिवारों के चिराग बुझा दिए गए और 42 साल बाद भी पीड़ित परिवारों के जख्म ताजा हैं। ऐसे संवेदनशील दिन पर राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा रामलीला मैदान में रैली आयोजित करना सिख समाज की भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस को पहले 1984 के पीड़ितों के न्याय और अपने इतिहास से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। ऐसे दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में राजनीतिक रैली आयोजित करने के फैसले ने सिख समाज की भावनाओं और पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर से सामने ला दिया है।

सिरसा ने कहा कि 42 वर्ष पहले जिन परिवारों ने अपने पिता, पति, बेटे और भाई खोए, वे आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आज हम राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के मामलों में लंबे समय तक न्याय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन मामलों को दोबारा गंभीरता से उठाया। दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने 1984 दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रति मृतक 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी और पीड़ितों की शिकायतों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति गठित की। इसके बाद फरवरी 2015 में केंद्र सरकार ने बंद हो चुके गंभीर मामलों की पुन: जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। सिरसा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य लंबे समय से लंबित न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी था। उन्होंने कहा कि आज जो लोग लोकतंत्र और इंसाफ की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1984 के पीड़ितों के लिए उनकी सरकारों ने क्या किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीड़ित परिवारों की शिकायतों को दोबारा सुना, अतिरिक्त मुआवजा दिया और बंद मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। न्याय की यह प्रक्रिया आज भी महत्वपूर्ण है। सिरसा ने रकाब गंज गुरुद्वारा हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि 1

नवंबर 1984 को वहां दो सिखों की हत्या हुई थी और इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच को लेकर वे स्वयं न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर अलग-अलग जांच और गवाहों के बयान सामने आए हैं, जबकि कमलनाथ ने आरोपों से इनकार किया है। 2019 में गृह मंत्रालय की एसआईटी ने 1984 से जुड़े सात मामलों को फिर से जांच के लिए लिया था, जिनमें रकाब गंज से संबंधित मामला भी शामिल था। सिरसा ने झारखंड के कांग्रेस नेता एवं मंत्री द्वारा दिल्ली में 10 हजार समर्थकों के साथ आकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कथित रूप से 'उठाकर रांची ले जाने' संबंधी बयान पर भी सवाल उठाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अंसारी ने यह बयान 1 नवंबर के विपक्षी प्रदर्शन के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को भीड़ तंत्र के बल पर उठाकर ले जाने की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती।

एक नजर

फरीदाबाद में प्रतिबंधित पटाखें बरामद, एक गिरफ्तार



फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा एवीटीएस भुपानी की टीम ने वजीरपुर गांव के पास से रविवार को राकेश को एक गौदाम से 70.780 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखों से भरे कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से राकेश निवासी गांव तिगांव फरीदाबाद को काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता अनुसार अपराध शाखा एवीटीएस भुपानी की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव वजीरपुर फरीदाबाद , में राकेश अवैध रूप से पटाखे बेचने का काम करता है तथा उसने बिक्री के लिए एक गोदाम में पटाखों से भरे प्लास्टिक कट्टे रखे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर राकेश को काबू किया। गोदाम के अंदर रखे प्लास्टिक कट्टों की जांच करने पर उनमें रॉकेट बम, सुतली बम, मुर्गा पटाखे, आकाश में छोड़ी जाने वाली आतिशबाजी, अनार, फुलझड़ी, फिरकी सहित विभिन्न प्रकार के 70.780 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे मिले। पटाखों को रखने एवं बेचने के संबंध में आरोपी से लाइसेंस व परमिट मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी राकेश के खिलाफ थाना खेडीपुल में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस : धर्मेन्द्र प्रधान

फरीदाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस को जब तक चुनाव में जीत मिलती है, तब तक ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया सही लगती है, लेकिन हारते ही उसे गड़बड़ी नजर आने लगती है। राहुल गांधी ने तीन बार चुनावी हार के बाद प्रधानमंत्री बनने के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे, वे टूट गए। अब कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को फरीदाबाद में भाजपा की पदयात्रा में पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी और उसके नेता राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्हें देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी संस्था पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस देश की बढ़ती ताकत को देख नहीं पा रही और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि अंगूर नहीं मिलते तो उन्हें खट्टा बताने लगती है। केरल और कर्नाटक में चुनाव जीतने पर उसे चुनाव प्रक्रिया सही लगती है, लेकिन बिहार, हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में हारने पर ईवीएम में गड़बड़ी नजर आने लगती है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी संसद में चर्चा नहीं कर सकती, वह रामलीला मैदान में क्या करेगी। प्रधान ने गांधी परिवार को लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि इसी परिवार ने संविधान में मनमाने संशोधन किए और देश में आपातकाल लगाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए के साथ पूरे देश में भीड़तंत्र को खत्म कर लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत एनआईटी के बीके चौक से हार्डवेयर चौक तक पदयात्रा निकाली। इसका नेतृत्व केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री एवं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इसमें गुरुग्राम के सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम, मंत्री राव नरबीर विधायक मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा और सतीश फागना सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से छिजारसी जाने वाले रास्ते पर भरेंगे गड्ढे

नोएडा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) होते हुए छिजारसी गोलचक्कर जाने वाले वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग पर हरनंदी तटबंध रोड के गहरे गड्ढों की मरम्मत कर सड़क को बेहतर बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग ने काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसी चयन के बाद मरम्मत शुरू होगी और काम छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार सड़क मरम्मत के लिए इच्छुक एजेंसियां 10 से 18 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में एजेंसियों के आवेदन और तकनीकी व अन्य मानकों की पूर्ति होने पर प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सकती है। ऐसे में दिसंबर में मौके पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

हरियाणा दिवस पर समारोह में ऐतिहासिक विरासत की दिखी झलक



गुरुग्राम। हरियाणा के छह दशकों की विकास यात्रा, ऐतिहासिक उपलब्धियों और समृद्ध लोक परंपराओं को उत्सव के रूप में मनाने के लिए रविवार को जिला प्रशासन गुरुग्राम की ओर से सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद सभागार (जॉन हॉल) में हीरक जयंती समारोह का आयोजित किया गया। समारोह में गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला तथा डीआईपीआरओ बिजेंद्र कुमार ने उनका स्वागत किया।

मुख्य अतिथि मेयर राजरानी मल्होत्रा ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस एवं हीरक जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने बीते 60 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रदेश ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। हरियाणा की असली ताकत यहां के मेहनतकश किसान, जवान, खिलाड़ी और कर्मठ नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। मेयर ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में रची-बसी लोक संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक मूल्य हमारी अमूल्य धरोहर हैं। समारोह में कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय हीरक जयंती समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। हरियाणवीं कलाकार मोंटी शर्मा के ग्रुप द्वारा रागनी, लोकगीतों तथा देव समाज स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक हरियाणवी लोकनृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से रूबरू कराया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने सभागार में हरियाणवी रंग और उत्सव का माहौल बना दिया। आयोजन स्थल पर हरियाणा के नक्शे और हीरक जयंती की थीम पर आधारित आकर्षक रंगोली भी बनाई गई, जो समारोह का विशेष आकर्षण रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता तिलकराज मल्होत्रा, एडीआईओ नवीन अहलावत, शिक्षा विभाग से एईओ जगदीश अहलावत, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल, सूबेदार बिजेंद्र सिंह ठाकरान, प्राचार्य संगीता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सिनेमैटिक हरियाणा एवं मिशन हरियाणा की ओर से हरियाणवी सिनेमा के गौरवशाली इतिहास और उसके विकास के सफर पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में हरियाणवी फिल्मों के शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान तक के सफर, उनके विकास और फिल्म जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को तस्वीरों एवं अन्य माध्यमों के जरिए आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर सिनेमैटिक हरियाणा के संस्थापक पुनीत शर्मा ने हरियाणवी सिनेमा पर विस्तार से प्रकाश डाला।

नूंह में सीआईए टीम और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली

नूंह। जिले में गौ तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय पुलिस टीम की रविवार को थाना सदर नूंह क्षेत्र के गांव घासेड़ा में एक कथित गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने रोकने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तीन गोवंश, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सीआईए स्टाफ नूंह के इंचार्ज निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गांव घासेड़ा में इंडियन पेट्रोल पंप के पास पीर मजार के नजदीक एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। घायल आरोपी की पहचान दिलशाद उर्फ दिल्ला निवासी गांव सुडाका, उम्र करीब 37-38 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन गाय, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में गौ तस्करी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नूंह में नकली पनीर के कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छह डेयरियों पर छापेमारी

नूंह। नूंह जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर झिरका तहसील के गांव गुज्जर नंगला में छह डेयरियों पर एक साथ छापेमारी की। उपायुक्त अखिल पिलानी के निर्देश पर शनिवार की देर रात चलाए गए इस अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने मौके पर मिले 5,319 किलोग्राम पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कराया। पनीर के सात नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए और 818 किलोग्राम संदिग्ध कच्ची सामग्री एवं रसायनों को सील किया गया। यह कार्रवाई एसडीएम फिरोजपुर झिरका रुहानी एस डी एम की मौजूदगी में चार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के छह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें शामिल रहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विकास जागलान ने बताया कि गांव गुज्जर नंगला स्थित छह डेयरियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पनीर निर्माण में इस्तेमाल की जा रही कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद हुईं। इनमें पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, सोया उत्पादों के अलावा रंग काटने वाला पदार्थ (रंगकट) और कपड़ों की सफेदी व चमक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसायन रैनिपाल फैब्रिक व्हाइटनर भी शामिल है। विभागीय टीम ने इन सामग्रियों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की।

छापेमारी के दौरान डेयरियों में मिला कुल 5,319 किलोग्राम पनीर प्रशासनिक निगरानी में गड्ढे में दबाकर नष्ट कराया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे पनीर को बाजार में पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। इसके अलावा अलग-अलग डेयरियों से पनीर के सात नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान एक डेयरी परिसर से 750 किलोग्राम मिल्क पाउडर, 60 किलोग्राम पाम ऑयल, पांच किलोग्राम रैनिपाल फैब्रिक व्हाइटनर और तीन किलोग्राम रंगकट बरामद किया गया। कुल 818 किलोग्राम संदिग्ध सामग्री एवं रसायनों को विभागीय टीम ने सील कर दिया। इनके इस्तेमाल और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है।

आजम खां की गिरफ्तारी कानून के तहत : बृजेश पाठक

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर जिला जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खां की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। कानून में कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। उन्होंने जो जुर्म किया है, उसके तहत कानून कार्य कर रहा है। यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को गाजियाबाद के पुलिस लाइन में आगमन के दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहीं।

यूपी के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का कार्य कानून व्यवस्था को मजबूत करने का है, जो कि उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में भाजपा सरकार के दौरान हुए सुधार हुआ है। इससे हर वर्ग के लोग संतुष्ट हैं। मजबूत कानून व्यवस्था और विकास के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। पाठक से जब दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सत्ता में आने की व्याकुलता है। इसी वजह से रैली का आयोजन किया जा रहा है। जनता के बीच कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में वाराणसी में भाजपा की हार के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है, अब तक की समीक्षा में जो एक वजह सामने आई है, वह वहां पर टिकट की घोषणा करने में देरी है। उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में लोकसभा चुनाव में हार और एमएलसी चुनाव में वाराणसी में हार का असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई नही देगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनना तय है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।

फरीदाबाद : निवेश के नाम पर मेडिकल स्टोर संचालक से ठगी, चार आरोपित गिरफ्तार



फरीदाबाद। शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने का लालच एक मेडिकल स्टोर संचालक से 15 लाख 71 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पंजाब निवासी प्रकाश, अनिरबान, असलम राणा उर्फ आशुतोष राणा तथा सन्नी सिंह के रुप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सैनिक कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित एक वीडियो देखा था। इसके बाद आरोपितों ने व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर निवेश करने के लिए कहा। शुरुआत में शिकायतकर्ता ने 10 हजार रुपये निवेश किए, जिसके बदले उन्हें 12 हजार 168 रुपये वापस मिले। इससे उन्हें आरोपितों पर विश्वास हो गया।

इसके बाद आरोपितों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग किस्तों में उनसे कुल 15 लाख 71 हजार रुपये निवेश करवा लिए। आरोपितों ने उनके ट्रेडिंग अकाउंट में करीब 19 लाख रुपये का मुनाफा दिखाया। जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो आरोपित टालमटोल करने लगे और उन्हें कोई पैसा वापस नहीं दिया। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित प्रकाश, अनिरबान और असलम उर्फ आशुतोष जीरकपुर की एक सोसायटी में रहते थे। आरोपित प्रकाश और अनिरबान ने अपना करंट बैंक खाता खुलवाकर असलम को दिया था। असलम ने उक्त बैंक खाते टेलीग्राम के माध्यम से सन्नी सिंह को भेजे थे। जिस खाते में साइबर ठगी की तीन लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। पुलिस ने चारों आरोपितों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

होटल में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी हुआ फरार

फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक होटल रूम में 35 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। युवती शनिवार को अपने प्रेमी के साथ होटल में आई थी। दोनों ने कपल बताकर कमरा नंबर 201 बुक कराया और दिनभर कमरे में ही रहे। दोपहर में दोनों ने साथ खाना भी खाया। देर रात होटल कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर गया तो युवती बेड पर मृत पड़ी थी, जबकि उसके साथ आया युवक मौके से गायब था। कर्मचारी ने शोर मचाया तो होटल मैनेजर और अन्य स्टाफ वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस युवती को तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को आशंका है कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। फिलहाल आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। युवती की पहचान बिहार के खड़गपुर की रहने वाली चांदनी (35) के रूप में हुई है। उसके साथ आए युवक ने अपना नाम शेखर दर्ज करवाया। वह भी बिहार का ही रहने वाला बताया जा रहा है।

वार्षिक खेल समापन समारोह खेलोत्सव-2026 का रंगारंग आगाज

गुरुग्राम। लायंस पब्लिक स्कूल सेक्टर-102 में वार्षिक खेल समारोह खेलोत्सव-2026 बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायन सुभाष धींगड़ा तथा उनकी धर्मपत्नी कृष्णा धींगड़ा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मशाल प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या अरुणा बहल ने स्वागत संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह अनुशासन और टीम भावना भी सिखाते हैं।

कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन लायन अशोक सोमल, उनकी धर्मपत्नी नीरू सोमल, सेक्रेटरी सुनील सिंगला, ट्रेजरर तरुण वाधवा, पूर्व चेयरमैन लायन एच.एल. डांग, लायन विजय बुद्धिराजा जैसे गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। स्कूल के प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा एवं ऊर्जा का शानदार प्रदर्शन करते हुए आकर्षक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज तथा संगीतमय योग प्रस्तुति दी, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस जैसी अनेक खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। समारोह में प्रस्तुत मनमोहक नृत्य ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में खेल ट्रॉफी का भव्य वितरण किया गया, जिसमें सभी विजेता विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरणों में शानदार प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हाउस को ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी प्रदान कर गौरवान्वित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन लायन डी.वी. तनेजा ने अपने प्रेरणादायक शब्दों एवं आशीर्वचनों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना। अंत में खेल महोत्सव का विधिवत समापन किया गया और प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। यह आयोजन विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना एवं स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को बढ़ावा देने का एक प्रेरणादायक माध्यम बना।

न सर्विस लेन, न लोडिंग-अनलोडिंग की जगह, एनएच-9 की खराब ट्रैफिक इंजीनियरिंग से लग रहा भीषण जाम

नोएडा,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डीएमई व एनएच-9 पर जिम्मेदारों की लापरवाही पलीता लगा रही है। जिस हाइवे का निर्माण लोगों की सुविधा को देखते हुए कराया गया था, वो ही लोगों की बड़ी परेशानी बन गया है। एनएचएआई की खराब ट्रैफिक इंजीनियरिंग व एनएच-9 का डिजाइन जाम का मुख्य कारण बन रहा है। नेशनल हाईवे पर जहां ऑटो प्रतिबंधित होते हैं और बसों का स्टॉप नहीं होता, वहीं ऑटो और बस यहां जाम का मुख्य कारण हैं। नियमों की अनदेखी के कारण यहां प्रतिदिन लाखों लोग जाम से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाम से मुक्ति नहीं मिल सकती।

छोटे-मोटे प्रयास किए जाएं तो यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मजबूत इच्छाशक्ति नहीं दिखा रहे। एनएच-9 का डिजाइन बनाते समय न तो सर्विस रोड दी गई और न लोडिंग व अनलोडिंग के लिए जगह दी गई। इसका नतीजा हुआ कि हाइवे पर ऑटो चालकों का कब्जा हो गया और बसों के स्टॉप से जाम लगने लगा। एनएच पर ऑटो व बस के खड़े होकर सवारी बैठाने से



वाहनों के निकलने के लिए जगह नहीं बचती और लंबा जाम लगता है। प्रतिदिन सुबह व शाम और त्योहारी सीजन में यातायात का दबाव बढ़ने से वाहनों की कई-कई किलोमीटर की कतार लग जाती है, जिसके चलते प्रतिदिन चार लाख से अधिक वाहन जाम में फंसते हैं। एनएच पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती तो की गई है लेकिन खराब ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कारण ये भी कुछ नहीं कर पाते। अगर एनएच पर बस व ऑटो का स्टॉप समाप्त कर दिया जाए तो काफी हद तक यहां जाम समाप्त किया जा सकता है।

पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर रोका तो पैदल ही रैली में चल दिए कांग्रेसी

गुरुग्राम। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में गुड़गांव से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, आमजन पहुंचे। जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर, जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) वर्धन यादव के नेतृत्व में जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गुड़गांव-दिल्ली बॉर्डर पर रोका, लेकिन वे वाहनों को छोड़कर पैदल ही दिल्ली की ओर चल दिए। शहर के सेक्टर-29 स्थित लेजरवैली मैदान से पूर्व सांसद राज बब्बर व पूर्व सांसद एवं रैली के गुड़गांव प्रभारी धर्मपाल मलिक भी रवानगी के दौरान मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गुड़गांव-दिल्ली बॉर्डर पर उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के आगे पुलिस को हटना पड़ा और सभी कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने काफी बसों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। काफी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते गए। कुछ समय बाद गाडियां निकलकर आई तो वे गाडियों में सवार हुए। जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि तानाशाही सरकार डर गई है। कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोका सरकार की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि जब सब



सेक्टर-29 लेजरवैली मैदान से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए निकले तो गुड़गांव-दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी की, लेकिन मजबूत इरादों के साथ हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ते गए। उन्होंने पूर्व सांसद राज बब्बर और धर्मपाल मलिक का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने सब कार्यकर्ताओं का हौंसला बढ़ाया है। जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) वर्धन यादव ने कहा कि सुबह जब हम निकले तो किसी ने नहीं सोचा था कि पुलिस हमें इस तरह रोकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता को रोक लोगे, लेकिन जनता के दिल में जो आक्रोश है, महंगाई, बेरोजगारी और इस तानाशाही के खिलाफ जो गुस्सा है, उसे कैसे रोकोगे।

अपराधियों के लिए कानून का भय क्यों नहीं?

सौरभ वार्ष्णेय



डिजिटल तकनीक ने जीवन को जितना सरल बनाया है, उतना ही साइबर अपराधियों के लिए ठगी के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों की जमा पूंजी लूटी जाती है, तो कभी पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर लोगों को भयभीत किया जाता है। वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी, सरकारी कार्यालयों जैसी पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी के कथित आदेश दिखाकर किसी व्यक्ति को घंटों या कई दिनों तक मानसिक दबाव में रखना तथा उससे धन हस्तांतरित करवाना इसी नए अपराध का खतरनाक रूप है। इसे आम बोलचाल में 'डिजिटल अरेस्ट' कहा जाता है। वास्तव में यह न तो कोई वैधानिक गिरफ्तारी है और न ही कानून की निर्धारित प्रक्रिया, बल्कि भय, भ्रम और तकनीक के दुरुपयोग से की जाने वाली संगठित ठगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को 'डिजिटल डकैती की संज्ञा देना इस अपराध की गंभीरता को रेखांकित करता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिस तरह ऐसे अपराधों पर कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता जताई है, उससे स्पष्ट है कि अब इस समस्या को केवल सामान्य ऑनलाइन धोखाधड़ी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनकी मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और कानून-व्यवस्था पर विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है। डिजिटल अरेस्ट की सबसे चिंताजनक विशेषता यह है कि इसमें अपराधी पीड़ित की कमजोरी, सामाजिक प्रतिष्ठा और कानून के प्रति सम्मान का फायदा उठाते हैं। किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से बताया जाता है कि उसके नाम से अवैध पार्सल भेजा गया है, बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है अथवा वह किसी गंभीर आपराधिक मामले में संदिग्ध है। इसके बाद फर्जी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी का प्रतिनिधि बनकर उसे गिरफ्तारी, जेल और परिवार की बदनामी का भय दिखाया जाता है। पीड़ित को किसी से बात न करने, घर में ही रहने और लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने का निर्देश दिया जाता है। अंतत: कथित जांच, सत्यापन या जमानत के नाम पर उससे लाखों रुपये तक वसूल लिए जाते हैं।

यह अपराध केवल धन की चोरी नहीं है। इसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से इस सीमा तक भयभीत कर दिया जाता है कि वह अपनी वर्षों की बचत, सेवानिवृत्ति के बाद मिला पैसा और कभी-कभी परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक अपराधियों के हवाले कर देता है। कई मामलों में पीड़ित अपनी समझ और विवेक से निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं रह जाता। यही कारण है कि डिजिटल अरेस्ट को केवल तकनीकी अपराध के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से की जाने वाली संगठित आर्थिक लूट के रूप में समझना आवश्यक है। इस अपराध में बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं विशेष चिंता का विषय हैं। जीवनभर की कमाई सुरक्षित रखने वाले वरिष्ठ नागरिक अक्सर कानून और सरकारी संस्थाओं के प्रति गहरा विश्वास रखते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो अनेक बुजुर्ग घबराकर उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अपराधी इसी भय का लाभ उठाते हैं। समाज में यह धारणा मजबूत करनी होगी कि किसी भी वास्तविक जांच एजेंसी को वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का नाटक करके किसी नागरिक से निजी बैंक खाते में पैसा जमा कराने का अधिकार नहीं है। न ही कोई वैध अधिकारी किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से ऑनलाइन हिरासत में रखकर धन हस्तांतरित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर भय पैदा करना उनकी प्रतिष्ठा पर भी हमला है। इसलिए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का उद्देश्य केवल धन की बरामदगी नहीं, बल्कि नागरिकों के मन से कृत्रिम भय को समाप्त करना भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गौरव कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका में 12 राज्यों में दर्ज 35 साइबर अपराध मामलों को एक स्थान पर लाने की मांग की गई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, आरोप है कि उनकी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और आगे भेजने के लिए किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे स्वयं धोखाधड़ी के शिकार हैं और उनकी जानकारी के बिना उनके खाते का इस्तेमाल हुआ।यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी उठाता है। साइबर ठगी की रकम अक्सर कई बैंक खातों से होकर गुजरती है। अपराधी दूसरों के खातों, कंपनियों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसे में किसी खाते में संदिग्ध धन आने मात्र से उसके संचालक को स्वत: दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। यह भी जरूरी है कि जांच एजेंसियां खाते के वास्तविक उपयोगकर्ता, धन के स्रोत, लेन-देन की प्रकृति, डिजिटल साक्ष्य और संबंधित व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच करें।दूसरी ओर, केवल यह दावा कर देना कि खाते का इस्तेमाल जानकारी के बिना हुआ, किसी व्यक्ति को स्वत: दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। जांच में सहयोग, उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल और धन के प्रवाह का पता लगाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि आरोपियों की सुविधा के लिए पीड़ितों को दिल्ली नहीं बुलाया जा सकता और अलग-अलग राज्यों में चल रही जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता, न्याय के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करती है। न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य आरोपियों की सुविधा से अधिक पीड़ितों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। हालांकि, मामलों को एक साथ जोडऩे या अलग-अलग राज्यों की जांच के समन्वय का प्रश्न तथ्यों और लागू कानून के आधार पर तय होना चाहिए। सख्ती का अर्थ यह नहीं कि किसी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। कठोर कार्रवाई और निष्पक्ष न्याय एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के दो आवश्यक आधार हैं।

डिजिटल ठगी के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे ही ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचती है, उसे कई स्तरों पर स्थानांतरित करके निकाल लिया जाता है। यदि जांच एजेंसियां समय रहते संदिग्ध धन पर रोक नहीं लगातीं, तो पीड़ित के लिए अपनी राशि वापस पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से ठोस साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध संपत्ति या खातों को कानून के अनुरूप फ्रीज करने की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल स्पष्ट कानूनी आधार, पर्याप्त सामग्री और आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति या वैध कारोबार का खाता बिना उचित आधार के लंबे समय तक बंद रहने से गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कार्रवाई के साथ समयबद्ध समीक्षा, प्रभावित व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी उपाय और जांच में पारदर्शिता भी जरूरी है। संपत्ति फ्रीज करना जांच का प्रभावी साधन होना चाहिए, न कि बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को दंडित करने का विकल्प। इसी संदर्भ में मुकदमे से पहले दंडित करने की किसी भी व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी आवश्यक है। अपराध से अर्जित धन को रोकना, संपत्ति को सुरक्षित करना और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर सजा देना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। संविधान और विधि के शासन के तहत अंतिम दंड का आधार विधिसम्मत प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय होना चाहिए। अपराध की गंभीरता के बावजूद निर्दोष होने की धारणा और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने और उसके लिए कठोर सजा निर्धारित करने पर विचार करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। मौजूदा कानूनों के अंतर्गत धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, आपराधिक धमकी, पहचान के दुरुपयोग और साइबर अपराध से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से कई मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। फिर भी डिजिटल अरेस्ट की विशिष्ट कार्यप्रणाली को देखते हुए कानून में स्पष्टता, जांच के मानक और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, केवल नया कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। साइबर अपराधी तकनीक और जांच से बचने के नए तरीके लगातार विकसित करते हैं। इसलिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाना, डिजिटल साक्ष्यों का त्वरित विश्लेषण करना, बैंकिंग संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना और ठगी की रकम के अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचना समान रूप से आवश्यक है। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए भी मजबूत तंत्र विकसित करना होगा। सरकार, बैंक, दूरसंचार कंपनियां और डिजिटल मंच इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संदिग्ध कॉल की पहचान, फर्जी नंबरों पर त्वरित कार्रवाई, खातों में असामान्य लेन-देन की निगरानी और शिकायत मिलने पर तत्काल प्रतिक्रिया जैसे कदम नुकसान कम कर सकते हैं। पुलिस को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए, ताकि पीड़ित शर्म या भय के कारण चुप न रहें।नागरिकों को भी कुछ बुनियादी सावधानियां अपनानी होंगी। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड या स्क्रीन साझा करने की अनुमति न दें। गिरफ्तारी या जांच के नाम पर किसी खाते में पैसा जमा न करें। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर धमकाता है, तो कॉल काटकर संबंधित एजेंसी के आधिकारिक माध्यम से सत्यापन करें। ठगी होने पर तत्काल बैंक को सूचित करें और भारत के साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। शुरुआती समय में की गई शिकायत धन को रोकने और साक्ष्य सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है।

बचपन अनुकरण की अवस्था है। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। वे माता-पिता की बातचीत, परिवार के सदस्यों के आचरण, मित्रों के व्यवहार और डिजिटल माध्यमों पर दिखाई देने वाली गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार-बार हिंसा, अपमान, बदले और आक्रामकता को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं तो उसके व्यवहार पर उनका प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि हर बच्चा ऐसी सामग्री देखकर हिंसक नहीं बनता लेकिन उम्र के अनुरूप सामग्री चुनना और उसके प्रभावों पर बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर व्यस्तता के कारण बच्चों को शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक, स्क्रीन एक आसान उपाय बन गई है। धीरे-धीरे यह आदत बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और अभिभावकों का ध्यान इस बात से हट जाता है कि बच्चा वास्तव में क्या देख रहा है। बच्चे का मोबाइल पर चुपचाप लगे रहना उसकी सुरक्षा या स्वस्थ विकास का प्रमाण नहीं है। डिजिटल दुनिया में उसकी गतिविधियों की जानकारी रखना, उम्र के अनुरूप सीमाएँ निर्धारित करना और उसके साथ नियमित संवाद बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों पर नजर रखने का अर्थ उन पर हर समय संदेह करना या उनकी निजता को पूरी तरह समाप्त कर देना नहीं है।

मोबाइल की दुनिया और बचपन का बिगड़ता व्यवहार

डॉ. प्रियंका सौरभ



पंचकूला के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा छह साल की बच्ची के साथ कथित क्रूर व्यवहार की खबर ने समाज को झकझोर दिया है। समाचार में सामने आए घटनाक्रम और विद्यालय परिसर में हुई हिंसा के विवरण ने बच्चों की सुरक्षा, उनके व्यवहार और हमारी परवरिश को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर बचपन में ऐसी हिंसक प्रवृत्तियाँ कैसे जन्म ले रही हैं? क्या बच्चों के भीतर संवेदनशीलता और सहानुभूति कम हो रही है? क्या मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक सामग्री और बदलते पारिवारिक वातावरण का उनके व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? इन सवालों से बचना अब संभव नहीं है। किसी एक घटना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि बच्चों में बढ़ती हिंसा का कारण केवल मोबाइल फोन है। प्रत्येक घटना के पीछे व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, पारिवारिक वातावरण, साथियों का प्रभाव, मानसिक स्थिति और सामाजिक परिवेश जैसे अनेक कारक हो सकते हैं। फिर भी यह सच है कि बच्चों के हाथों में पहुँच चुकी डिजिटल दुनिया ने माता-पिता की जिम्मेदारियों को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। अब बच्चों की निगरानी केवल स्कूल से लौटने के बाद उनके व्यवहार तक सीमित नहीं रह सकती। यह जानना भी आवश्यक है कि वे मोबाइल पर क्या देखते हैं, किन लोगों से बातचीत करते हैं, कौन-से खेल खेलते हैं और इंटरनेट से किस प्रकार के विचार ग्रहण कर रहे हैं। आज स्मार्टफोन बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, शैक्षिक वीडियो और ज्ञानवर्धक सामग्री के माध्यम से तकनीक ने सीखने के नए अवसर खोले हैं। लेकिन इसी माध्यम पर हिंसक दृश्य, अपमानजनक भाषा, खतरनाक चुनौतियाँ और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। समस्या तकनीक के अस्तित्व में नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग, अनुचित सामग्री तक पहुँच और उसके प्रभावों को समझने की कमी में है। बच्चे कई बार मनोरंजन के नाम पर ऐसी सामग्री देखते हैं, जिसके परिणामों को समझने के लिए वे मानसिक और भावनात्मक रूप से पर्याप्त परिपक्व नहीं होते।

बचपन अनुकरण की अवस्था है। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। वे माता-पिता की बातचीत, परिवार के सदस्यों के आचरण, मित्रों के व्यवहार और डिजिटल माध्यमों पर दिखाई देने वाली गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार-बार हिंसा, अपमान, बदले और आक्रामकता को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं तो उसके व्यवहार पर उनका प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि हर बच्चा ऐसी सामग्री देखकर हिंसक नहीं बनता लेकिन उम्र के अनुरूप सामग्री चुनना और उसके प्रभावों पर बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर व्यस्तता के कारण बच्चों को शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक, स्क्रीन एक आसान उपाय बन गई है। धीरे-धीरे यह आदत बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और अभिभावकों का ध्यान इस बात से हट जाता है कि बच्चा वास्तव में क्या देख रहा है। बच्चे का मोबाइल पर चुपचाप लगे रहना उसकी सुरक्षा या स्वस्थ विकास का प्रमाण नहीं है। डिजिटल दुनिया में उसकी गतिविधियों की जानकारी रखना, उम्र के अनुरूप सीमाएँ निर्धारित करना और उसके साथ नियमित संवाद बनाए रखना आवश्यक है। बच्चों पर नजर रखने का अर्थ उन पर हर समय संदेह करना या उनकी निजता को पूरी तरह समाप्त कर देना नहीं है। इसका अर्थ है उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहना और ऐसा विश्वासपूर्ण वातावरण बनाना, जिसमें वे अपनी परेशानी, जिज्ञासा और गलतियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। माता-पिता को बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कौन-से खेल खेलते हैं, इंटरनेट पर क्या नया देखते हैं और किसी वीडियो या घटना के बारे में उनकी क्या समझ है। यदि बच्चा किसी हिंसक दृश्य को देखकर उत्साहित होता है, किसी को चोट पहुँचाने की बात करता है या उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आता है तो उसे केवल डाँटकर चुप कराने के बजाय कारण समझने का प्रयास करना चाहिए।

विद्यालयों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं है। विद्यालय बच्चों को संवेदनशील, जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने का भी माध्यम हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार में आने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में परामर्श व्यवस्था, भावनात्मक शिक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और दूसरों की गरिमा का सम्मान करने से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के बीच मारपीट, धमकी, अपमान या किसी कमजोर विद्यार्थी को निशाना बनाने की घटनाओं को सामान्य शरारत समझकर टालना भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही, किसी बच्चे द्वारा गंभीर गलती किए जाने पर उसके व्यवहार की जवाबदेही तय करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि जाँच और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो। बच्चों को अपराधी घोषित करने की जल्दबाजी, सार्वजनिक अपमान या सोशल मीडिया पर उनकी पहचान उजागर करना उचित नहीं है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में हिंसा, असामान्य आक्रामकता या भावनात्मक संकट के संकेत दिखाई दे तो अभिभावकों और विद्यालयों को योग्य बाल मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। डिजिटल मंचों और सरकार की भूमिका पर भी विचार करना होगा। बच्चों के लिए अनुचित सामग्री तक पहुँच रोकने, अभिभावकीय नियंत्रण के साधनों को सरल बनाने और आयु के अनुरूप डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इंटरनेट कंपनियों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन किसी तकनीकी सुविधा पर पूरी तरह निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना सीखना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सही, सुरक्षित या अनुकरण करने योग्य नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को केवल नियमों से नहीं, उदाहरणों से भी सिखाया जाता है। यदि घर में गुस्से के समय अपशब्दों का प्रयोग होता है, विवादों का समाधान मारपीट से किया जाता है और दूसरों के प्रति अपमानजनक व्यवहार सामान्य माना जाता है तो बच्चों से पूर्णत: विपरीत आचरण की अपेक्षा करना कठिन होगा। परिवार में संवाद, धैर्य, सहानुभूति और सम्मान का वातावरण बनाना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें खेलकूद, पुस्तक-पठन, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल के अवसर देना भी जरूरी है। पंचकूला की घटना से उपजे सवाल केवल एक विद्यालय या एक परिवार तक सीमित नहीं हैं। वे पूरे समाज के सामने एक चेतावनी की तरह खड़े हैं। हमें बच्चों को तकनीक से दूर रखने की बजाय उसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सिखाना होगा। मोबाइल पर वे क्या देख रहे हैं, यह जानने के साथ-साथ यह भी समझना होगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं वे अकेलेपन, तनाव, उपेक्षा या किसी अनकही परेशानी से तो नहीं जूझ रहे? बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पहले उन्हें विवेक देना, स्वतंत्रता देने से पहले जिम्मेदारी सिखाना और अनुशासन के साथ स्नेह देना आज समय की मांग है।

विचार

चक्रवातों के साये में तटीय भारत का भविष्य

डॉ. प्रियंका सौरभ

समुद्र जितना जीवनदायी है, उसका रौद्र रूप उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बेहद अहम है लेकिन यही तटीय क्षेत्र हर साल चक्रवातों, समुद्री तूफानों, बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा भी झेलते हैं। चक्रवात अर्नब ने एक बार फिर तटीय भारत की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि चक्रवात कब और कहां आएगा बल्कि यह भी है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बदलते मौसम के दौर में अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से नुकसान कम करने की रणनीति बनानी होगी। चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बचता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें और नदियों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। तटीय क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा भी बड़ी समस्या है। चक्रवात के दौरान बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संचार सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। इससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। कई तटीय शहरों में अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निचले इलाकों में बस्तियों का विस्तार खतरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को बचाने के साथ-साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली पहले से बेहतर हुई है लेकिन चुनौती अब भी यह है कि चेतावनी समय पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों, दूरदराज के गांवों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों तक सूचना पहुंचाना आसान नहीं है।

कई बार लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते या घर और आजीविका छोड़ने के डर से सुरक्षित स्थानों पर जाने में देरी करते हैं। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों को उसके खतरे और उससे बचने के उपायों के बारे में समझाना भी जरूरी है। चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की चिंता सताती है। चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी भर जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कमजोर होना भी चिंता का विषय है। मैंग्रोव वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों का विनाश और समुद्र तटों पर बढ़ता निर्माण चक्रवातों के खतरे को बढ़ाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री लहरों की ताकत कम करने और तटीय इलाकों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास भविष्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा। मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ उपग्रहों, डॉप्लर रडार और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार जरूरी है। चेतावनी केवल मोबाइल संदेशों तक सीमित न रहे। सायरन, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। चेतावनी स्थानीय भाषा में हो और उसमें यह साफ बताया जाए कि लोगों को क्या करना है और कहां जाना है। इसके साथ ही तटीय इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। चक्रवात आश्रयस्थलों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित निकासी मार्ग बनाने और अस्पतालों, बिजलीघरों तथा पेयजल व्यवस्था को आपदा के लिहाज से मजबूत करने की जरूरत है। आश्रयस्थलों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नियमित मॉक ड्रिल से लोगों को आपदा के समय सही कदम उठाने का अभ्यास कराया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, मछुआरा समितियों और युवाओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूलों में आपदा संबंधी जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए।

एक नजर

निशांत के नेतृत्व में यूपी जदयू ने भरी हुंकार, वाराणसी का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन एक नए युग का शंखनाद : उमेश सिंह कुशवाहा



पटना। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लोकप्रिय नेता निशांत के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जदयू के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश में निशांत का प्रथम संगठनात्मक एवं राजनीतिक दौरा अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है। वाराणसी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्हें सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा, वह वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय था। कुशवाहा ने कहा कि निशांत के उद्बोधन ने यूपी के जमीनी कार्यकर्ताओं में जिस नए उत्साह, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना का संचार किया है, वह आने वाले समय में यूपी जदयू के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। एक कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में निशांत ने जनसेवा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उनकी गूंज आज बिहार की सीमाओं को पार कर पूरे भारत में सुनाई दे रही है। यही कारण है कि बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों के युवाओं और आम जनमानस के बीच निशांत की लोकप्रियता एवं जनस्वीकृति में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश की धरती पर निशांत के इस शानदार राजनीतिक आगाज का प्रभाव आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में देखने को मिलेगा। उनके नेतृत्व में न्याय के साथ विकास और सुशासन की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में नई मजबूती मिलेगी।

हटवारिया गांव पहुंचे सांसद दिलेश्वर कामत, पीड़ित परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस

सुपौल। पिपरा थाना क्षेत्र के हटवारिया गांव में मजदूर उपेंद्र सादा की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने रविवार को सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने इस संबंध में सुपौल के एसपी से भी बातचीत की है। पांच दिन पूर्व पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 15 स्थित हटवारिया गांव में एक मजदूर का शव नदी किनारे मिला था। मृतक की पहचान उपेंद्र सादा उर्फ तिरन सादा के रूप में हुई थी। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। परिजनों ने आशंका जताई थी कि उपेंद्र सादा की हत्या कर शव को नदी किनारे फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके



पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं, परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताए जाने के बाद मामले को लेकर गांव में भी चर्चा बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार को सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत हटवारिया गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। घटना में जो भी दोषी होंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सांसद ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुपौल के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा भी दिया। इस मौके पर निर्मली पंचायत के मुखिया हरिनंदन मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटरों का जोरदार प्रदर्शन, सरकारी काम ठप करने की दी चेतावनी

भागलपुर। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा की भागलपुर इकाई के बैनर तले रविवार को डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी मांगों के समर्थन में भागलपुर समाहरणालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द सेवा नियमित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग उठाई। कर रहे ऑपरेटरों ने कहा कि वे वर्ष 1997 से राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक तरफ सरकार लगातार सरकारी कार्यालयों को डिजिटल और हाईटेक बनाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वर्षों से इन विभागों को डिजिटल बनाने में रीढ़ की हड्डी बने डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जायज मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। ऑपरेटरों का साफ तौर पर कहना है कि जब सरकार उनकी मूलभूत मांगों को ही पूरा नहीं कर रही है, तो सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह डिजिटल बनाने का सरकार का सपना कैसे पूरा होगा? संघ के जिला प्रवक्ता गौरव कुमार झा ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, 'हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। अगर हमारी मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो हम सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सभी सरकारी कार्यालयों के कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर समाहरणालय गेट पर मौजूद रहे और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस आंदोलन के बाद अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।

मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड के कमांड सेंटर का किया उद्घाटन, 1.06 लाख दुग्ध उत्पादकों के खातों में 68.51 करोड़ रुपये ट्रांसफर

पटना,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना स्थित कॉम्फेड में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित कॉल सेंटर 'सुधा संपर्क' का भी उद्घाटन किया। इसे पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डीबीटी के माध्यम से 5,832 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े 1,06,063 लाभार्थियों के बैंक खातों में 68 करोड़ 51 लाख 27 हजार 60 रुपये (करीब 68.51 करोड़ रुपये) की राशि हस्तांतरित की। यह भुगतान 1,46,66,061 लीटर दूध की आपूर्ति के एवज में किया गया।



कार्यक्रम के दौरान डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कॉम्फेड की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'सुधा' का विस्तार बिहार से बाहर भी किया जा रहा है। असम के तेजपुर में प्रतिदिन 20 हजार लीटर क्षमता वाली इकाई शुरू हो चुकी है। असम में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की एक अन्य इकाई और कोलकाता में 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की इकाई स्थापित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गठित करने का लक्ष्य है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 4,804 नई समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल 33,897 समितियां सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 23.90 लाख किलोग्राम दूध का संग्रहण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुग्ध संग्रहण और परिवहन व्यवस्था की रियल टाइम निगरानी के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18003456199 पर 'सुधा संपर्क' कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा 3,200 'सुधा सखी' तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जीविका के सहयोग से 31 मार्च 2027 तक राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में 'जीविका-सुधा बिक्री केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं को पशु औषधि बिक्री केंद्रों के संचालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुओं की नस्ल सुधार, बेहतर पोषण और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स-सॉर्टेड सीमेन के उपयोग, डुमरांव में बछिया पालन केंद्र, मुंगेर में सीमन स्टेशन और 12 टोटल मिक्स्ड राशन (टीएमआर) संयंत्र स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों को बेहतर बाजार देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के दूध, सब्जियों और मछली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों से मुक्त कर पारदर्शी तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों के हित में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को यूनिक फार्मर आईडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से दूध की गुणवत्ता, फैट और एसएनएफ की मात्रा तथा भुगतान की डिजिटल निगरानी संभव होगी।

त्योहारों की थाली पर खाद्य सुरक्षा का पहरा, सीवान में छापेमारी में खुली लापरवाही की पोल

सीवान। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के कचहरी ढाला के समीप संचालित पवन बिरियानी में छापेमारी की तो खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी की कई गंभीर बातें सामने आईं। प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार का वैध लाइसेंस नहीं था।

भोजन तैयार करने के लिए व्यवस्थित किचेन तक उपलब्ध नहीं मिला। मटन और चिकेन खुले में तैयार किए जा रहे थे, जबकि भोजन को धूल, गर्दा और मक्खियों से बचाने का कोई समुचित इंतजाम नहीं था। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के निर्देश पर 'थाली शुद्ध होबे हमार, छठ-दीपावली' अभियान के तहत एक से सात नवंबर तक जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन निरीक्षी पदाधिकारी संतोष कुमार सिन्हा और खाद्य संरक्षा पदाधिकारी डॉ. विपुल कुमार की टीम ने शहर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पवन बिरियानी की जांच में संचालक खाद्य कारोबार से संबंधित कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। डॉ. विपुल कुमार के अनुसार, प्रतिष्ठान न तो होटल-रेस्टोरेंट श्रेणी में पंजीकृत है और न ही ठेला-खोमचा श्रेणी में इसका लाइसेंस मिला। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर बिरियानी तैयार कर ग्राहकों को परोसी जा रही थी। जांच के दौरान ग्राहकों को दिए जा रहे बोतलबंद पानी पर बैच नंबर और आवश्यक विवरण भी नहीं मिले। भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे तेल की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। दुकान संचालक पवन ने सफाई देते हुए कहा कि वह लंबे समय से इसी तरह भोजन परोस रहे हैं और ग्राहक इसे पसंद करते हैं। हालांकि, उन्होंने सड़क किनारे दुकान होने के कारण धूल और मक्खियों की आशंका स्वीकार की। खाद्य सुरक्षा टीम ने पवन बिरियानी के अलावा अपूर्वा स्वीट्स, कुमार स्वीट्स, प्रिया स्वीट्स, हरिलाल रेस्टोरेंट और जैन स्वीट्स सहित कई प्रतिष्ठानों की भी जांच की। डॉ. विपुल कुमार ने बताया कि जांच के दौरान विभिन्न दुकानों में अनियमितताएं मिली हैं। संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर नियमानुसार फॉर्म-ङ्क्र भरा गया है। नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा।

66.50 लाख जब्त रुपए मामले में दो महिला सहित तीन आरोपित गिरफ्तार

डेहरी आन सोन। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान की गई कार्रवाई में 66 लाख 50 हजार रुपये नकद जब्त करते हुए दो महिला सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने काले रंग की एक्सयूवी-300 कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार शनिवार की रात शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह को सूचना मिली कि वाराणसी की ओर से आ रही काले रंग की एक्सयूवी-300 कार (रजिस्ट्रेशन नंबर ब्क्र-24रु-9617) में भारी मात्रा में नकद राशि ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर एनएच-19 स्थित शिवसागर टोल टैक्स के पास वाहन जांच शुरू की।

रात करीब 9 बजे संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने पीछा कर वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान कार में चालक के साथ बैठी दो महिलाओं के पास से नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान चंदन कुमार की पत्नी ज्योति कुमारी (30), परमानंद सोनी की पत्नी पूनम कुमारी (34) और गोपाल प्रसाद के पुत्र चंदन कुमार (32) तीनों निवासी नवरत्न बाजार सासाराम, जिला रोहतास के रूप में हुई है। एसडीपीओ एक विप्लव कुमार ने बताया कि तलाशी में चालक चंदन कुमार के सीट कवर के नीचे से 4.50 लाख रुपये, ज्योति कुमारी के बदन में छिपाकर रखे 26 लाख रुपये और पूनम कुमारी के पास से 36 लाख रुपये बरामद किए गए। इस प्रकार कुल 66.50 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि बरामद नकदी के संबंध में संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई जा रही थी और इसका उद्देश्य क्या था। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि जब्त रूपया मामले टीम में थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह , पुलिस अवर निरीक्षक विनोद यादव , सतीश सिंह , धर्मेंद्र कुमार , जया भारती एवं थाने के पुलिस जवान शामिल थे।

एनएफआर के नवनियुक्त जीएम विवेक खरे का कटिहार में भव्य स्वागत, सुरक्षा व यात्री सुविधाओं पर रहेगा जोर

कटिहार। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के नवनियुक्त महाप्रबंधक विवेक खरे के रविवार को कटिहार आगमन पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) किरेन्द्र नरह एवं अन्य वरीय रेल अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद महाप्रबंधक के पहले आगमन से एनएफआर क्षेत्र में बुनियादी रेल विकास, परिचालन सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

आगमन के दौरान डीआरएम किरेन्द्र नरह ने महाप्रबंधक को कटिहार मंडल में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा संरक्षा से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। नवनियुक्त महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि एनएफआर में रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक सिग्नलिंग और उन्नत सुरक्षा तकनीक 'कवच' के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार, माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि, नई रेल लाइनों के निर्माण, विद्युतीकरण और ट्रैक दोहरीकरण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कटिहार सहित अलीपुरद्वार, लुमडिंग, रंगिया और तिनसुकिया मंडलों में चल रही विकास परियोजनाओं और रेल परिचालन की नियमित समीक्षा की जाएगी। नवनियुक्त रेल महाप्रबंधक विवेक खरे भारतीय रेल यांत्रिक अभियंता सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। 3 मार्च 1991 से रेल सेवा शुरू करने वाले श्री खरे के पास तीन दशक से



अधिक का व्यापक तकनीकी व प्रशासनिक अनुभव है। अपने सेवाकाल के दौरान वे दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा व सिकंदराबाद मंडल, लालागुड़ा वर्कशॉप, तुगलकाबाद डीजल शेड, राइट्स और आरडीएसओ लखनऊ में प्रमुख पदों पर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रायपुर में अपर मंडल रेल प्रबंधक, चारबाग वर्कशॉप में वरिष्ठ प्रशासनिक पद तथा मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) रायबरेली में प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (पीसीएमई) के साथ जीएम का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। स्वागत समारोह के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) मनोज कुमार सिंह, सीनियर डीईएन (समन्वय) प्रभात रंजन सिंह, आरपीएफ कमांडेंट संदीप कुमार पीएस सहित मंडल के सभी प्रमुख शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ेगा एसोसिएशन, छह माह पर होगी कार्यशाला

पश्चिम चम्पारण। ग्रामीण पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन स्थानीय से प्रदेश स्तर तक पहल करेगा। संगठन की मजबूती, पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और आधुनिक तकनीक से उन्हें अवगत कराने के लिए प्रत्येक छह माह पर कार्यशाला आयोजित की जायेगी। रविवार को प्रखंड बगहा-दो के सभागार में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में इस आशय के प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष इसराइल अंसारी ने की, जबकि संचालन चंद्रभूषण शांडिल्य ने किया। बैठक में बगहा पुलिस जिले के विभिन्न प्रखंडों में संगठन का विस्तार करने तथा पत्रकारों को एकजुट कर उनके हितों के लिए संघर्ष करने पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि बगहा, रामनगर, पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकरहा में संगठन की अगली बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में तिथि, समय और स्थान निर्धारित किए जायेंगे।

जिला अध्यक्ष इसराइल अंसारी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी सदस्यों को निर्धारित नियमों और नीतियों का पालन करना होगा। प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों की सदस्यता के संबंध में भी स्पष्ट नीति के अनुरूप कार्य किया जाएगा। संगठन के मंत्री अबू साबिर ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में कोई



सदस्य छोटा या बड़ा नहीं है। संगठन की वास्तविक पहचान उसके कार्यों, एकजुटता और पत्रकारों के प्रति समर्पण से बनती है। उन्होंने सभी सदस्यों से संगठनात्मक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की अपील की। वरिष्ठ पत्रकार एवं संगठन के संरक्षक मधुरेंद्र पांडेय ने कहा कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार से पत्रकारिता के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। इस दौर में प्रिंट मीडिया के सामने भी नई चुनौतियां हैं। ऐसे में पत्रकारों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता करने की अपील की। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रो.डॉ.अरविंद नाथ तिवारी ने कहा कि पत्रकार की कलम में व्यवस्था और सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। स्वतंत्रता सेनानी एवं निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की बुनियाद सच्चाई, निर्भीकता और जनहित है। उन्होंने वर्तमान समय में मीडिया के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और संपादकीय स्वतंत्रता के सवाल पर भी चिंता व्यक्त की। प्रो. तिवारी ने पत्रकार पेंशन योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से घोषणा किए जाने के बावजूद बहुत कम पत्रकारों को इसका लाभ मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बीच काम करने वाले पत्रकारों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रस्ताव तैयार कर सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेगा।

राजकीय पॉलिटेक्निक में तीन दिवसीय सघन भौतिक सत्यापन प्रक्रिया संपन्न, दो शाखाओं को मिलेगी वैश्विक पहचान

कटिहार। राजकीय पॉलिटेक्निक, कटिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की तीन दिवसीय सघन भौतिक सत्यापन प्रक्रिया रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चले इस मूल्यांकन के तहत एनबीए की तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम (एक चेयरमैन और दो ब्रांच एक्सपर्ट) ने संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रयोगशालाओं, आधारभूत संरचना और 'आउटकम बेस्ड एजुकेशन' (ओबीई) के क्रियान्वयन की विस्तृत जांच की।

सत्यापन के अंतिम दिन आयोजित 'एनबीए एग्जिट मीटिंग' में विशेषज्ञों ने संस्थान की शिक्षण-अधिगम (टीचिंग-लर्निंग) प्रक्रिया को उत्कृष्ट बताते हुए छात्र-छात्राओं के उच्च अनुशासन और व्यवहार की विशेष सराहना की। टीम ने संस्थान के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। संस्थान के प्राचार्य डॉ. रवि कुमार ने एनबीए टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों शाखाओं को मान्यता मिलने से संस्थान की साख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी। इससे उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं की डिग्री को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, जिससे उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता हासिल होगी। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को सभी शिक्षकों, विभागाध्यक्षों और कर्मियों के अथक परिश्रम व सामूहिक टीम भावना का परिणाम बताया। तीन दिवसीय निरीक्षण को सुचारू रूप से संचालित कराने में संस्थान के एनबीए समन्वयक इंजी. चंदन शॉ की भूमिका प्रमुख रही, जिन्होंने तीनों दिन एनबीए टीम के साथ



समन्वय स्थापित कर अभिलेखों और प्रस्तुतियों का कुशल प्रबंधन किया। विभागीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाध्यक्ष इंजी. अभिषेक मंकर और मैकेनिकल विभागाध्यक्ष इंजी. नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीमों ने लैब और पाठ्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों का सफल सत्यापन कराया। इसके अलावा प्रथम वर्ष के शिक्षकों ने शैक्षणिक सहयोग तथा इंजी. हिमांशु, इंजी. कुंदन और इंजी. सुजीत ने टीम प्रबंधन व आतिथ्य की जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक संभाली।

एक नजर

दूसरा अनौपचारिक टेस्टः बॉयल के शतक और फॉक्सक्रॉफ्ट के अर्धशतक से न्यूजीलैंड ए मजबूत

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड)। न्यूजीलैंड ए ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को मैथ्यू बॉयल के शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के अर्धशतक की बदौलत अच्छी वापसी की। इससे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने तीन विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए हैं। टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 128 रन पीछे है। मैथ्यू बॉयल 148 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 107 रन और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 180 गेंदों में 80 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 205 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है, जिसने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबार कर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इससे पहले इंडिया ए की पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने शतक लगाया। वह 171 गेंदों में 105 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए। इसके अलावा आकाशदीप ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए। इन दोनों की पारियों की बदौलत भारत पहली पारी में 346 रन बनाने में सफल रहा। इंडिया ए के लिए पहली पारी में साई सुदर्शन ने 41 और देवदत्त पडिक्कल ने भी 80 रन की पारी खेली थी।

346 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ए की शुरुआत खराब रही। कप्तान रीस मारियू 4 रन, कर्टिस हेफी 4 रन और टिम रॉबिन्सन 3 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद मैथ्यू बॉयल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए वापसी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ए भारत के पहली पारी के स्कोर से 128 रन पीछे है और उसके सात विकेट शेष हैं। ऐसे में तीसरा दिन मुकाबले के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम में बदलाव

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में बदलाव किया है। यह मैच पांच नवंबर से सिलहट (बांग्लादेश) में खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि मोमिनुल हक की जगह अमिते हसन को टीम में शामिल किया गया है। मोमिनुल 'कन्कशन' (सिर की चोट) के कारण अनिवार्य सात दिनों के आराम (स्टैंड-डाउन पीरियड) पर हैं इसलिए वे उपलब्ध नहीं हैं। पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग करते समय सिर में चोट लगने के कारण मोमिनुल हक टीम से बाहर हुई हैं। मैच के दौरान उनकी जगह जाकेर अली को मैदान में उतारा गया था। आईसीसी के कन्कशन दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें वापसी से पहले कम से कम सात दिन का अनिवार्य विश्राम करना होगा। टीम में शामिल किए गए विकेटकीपर-बल्लेबाज अमिते हसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पदार्पण किया था। अभी तक हसन ने केवल एक टेस्ट मैच खेला है। हालांकि उनके पास घरेलू क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 54 मैचों में 50.50 के औसत से 4040 रन बनाए हैं। पहले टेस्ट में हार के कारण बांग्लादेश की टीम मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में चौथे से फिसलकर पांचवें स्थान पर आ गई है।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश की टीम

नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), शादमान इस्लाम, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, लिटन दास, जाकेर अली, मेहदी हसन मिराज, नईम हसन, हसन महमूद, तैजुल इस्लाम, शरिफुल इस्लाम, मुश्फिकुर रहीम, तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, अमिते हसन।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका : दक्षिण अफ्रीका की टॉप-2 में वापसी, न्यूजीलैंड टॉप पर

नई दिल्ली। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 की अंक तालिका में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने के बाद मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर टॉप-2 में जगह बना ली है। वहीं, न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका की जीत से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है और टीम अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत चौथे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश पांचवें नंबर पर मौजूद है। अभी डब्ल्यूटीसी चक्र में कई अहम टेस्ट सीरीज बाकी हैं। ऐसे में आने वाले मुकाबले अंक तालिका की तस्वीर बदल सकते हैं। आइए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की सीरीज जीत के बाद डब्ल्यूटीसी की ताजा स्थिति क्या है-

आईसीसी के अनुसार न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी कीवी टीम ने दमदार खेल दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद न्यूजीलैंड ने लगातार दो मुकाबले जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस तरह टीम ने छह मैचों में चार जीत के साथ अपना अंक प्रतिशत 72.22 कर लिया है। न्यूजीलैंड को आगे भारत और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का दौरा भी करना है। ये मुकाबले फाइनल की राह में काफी अहम होंगे।

मौजूदा डब्ल्यूटीसी चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू सीरीज में 2-1 से हराकर शानदार वापसी की है। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में प्रोटियाज टीम पहले मुकाबले में हार गई थी, लेकिन इसके बाद उसने लगातार दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले टीम ने भारत को उसकी धरती पर 2-0 से हराया था और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज ड्रॉ खेली थी। दक्षिण अफ्रीका को अब बांग्लादेश और इंग्लैंड की मेजबानी करनी है, जबकि आखिरी सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करना होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 अभियान की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की थी। टीम ने वेस्टइंडीज को उसके घर में हराया और घरेलू मैदान पर एशेज सीरीज भी अपने पास बरकरार रखी। हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ मिली अप्रत्याशित हार ने टीम को झटका दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को डरबन टेस्ट में 214 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार दो मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा खत्म कर दिया। इस हार के कारण ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में पहले स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

अंतिम टी-20 में न्यूजीलैंड की सात विकेट से जीत, भारत ने 3-2 से सीरीज अपने नाम की

हैमिल्टन (न्यूजीलैंड)। न्यूजीलैंड टीम ने पांचवें और अंतिम टी-20 मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 191 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 192 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बावजूद भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की। भारत ने सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबले जीते थे। इसके बाद पांचवें और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड ने जीत के साथ सीरीज का समापन किया। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी के दूसरे ओवर में फिन एलन दो रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू किए और पावरप्ले के छह ओवर में टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 59 रन बटोरे।

न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 82 रन के स्कोर पर गिरा, जब डेरिल मिचेल 16 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टिम साइफर्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने 50 गेंदों में 11 चौके और पांच छक्कों की मदद से 93 रनों की तेज पारी खेली। साइफर्ट 16वें ओवर में 168 रन के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। हालांकि तब तक न्यूजीलैंड की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स 38 गेंदों में 65 रन और बेवॉन जैकब्स एक रन बनाकर नाबाद रहे।



भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 191 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़े। ईशान ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से 61 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। ईशान और श्रेयस के अलावा नमन धीर ने 23 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाए। नीतीश ने 17 गेंदों पर 22 रन का योगदान दिया। वहीं, संजू सैमसन चार रन, अभिषेक शर्मा एक रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और भुवनेश्वर कुमार ने छह-छह रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को दो-दो सफलताएं मिलीं।

गेंदबाजी और फील्डिंग में बेहतर कर सकते थे, हार के बाद बोले श्रेयस अय्यर

हैमिल्टन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, भारतीय टीम ने शुरुआती तीन मुकाबलों में जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। मैच के बाद भारतीय टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार के कारणों पर बात करते हुए कहा कि टीम मध्य ओवरों में मिली अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही। उन्होंने माना कि गेंदबाजी और फील्डिंग में बेहतर कर सकते थे।

श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम बेहतर कर सकते थे। मध्य के ओवरों में हमें जो शुरुआत मिली थी और जिस तरह से ईशान और मैंने गति बनाई थी, उसे देखते हुए हम और बेहतर कर सकते थे। लेकिन हमने लगातार विकेट गंवा दिए, जिससे नए बल्लेबाज पर दबाव आ गया। उन्होंने कहा कि इस विकेट पर खेलना आसान नहीं था, खासकर तब जब गेंद सीम कर रही थी, थोड़ी रुक कर आ रही थी। यह काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि 191 रन एक ठीक-ठाक स्कोर था। मुझे लगता है कि हम अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर कर सकते थे। अय्यर ने कहा कि यह सीखने का एक बहुत अच्छा मौका रहा। न्यूजीलैंड आना और अलग-अलग मैदानों पर खेलना, सीखने का एक शानदार अनुभव रहा। भारतीय टी-20 कप्तान ने कहा कि पहले तीन मैचों ने हम एक अच्छी लय दी। आखिरी दो मैचों में हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम कुछ प्रयोग करना चाहते थे और खुद को थोड़ा और चुनौती देना चाहते थे। हालांकि जैसा मैंने कहा, यह सीखने का एक बेहतरीन मौका था। उन्होंने कहा कि जब आप विदेश में खेलने जाते हैं तो खेल के अलग-अलग पहलुओं में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आप जितनी हिम्मत के साथ इन चुनौतियों का सामना करते हैं, चीजें उतनी ही बेहतर होती जाती हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे पास एक ऐसा ही मौका था जिसका हम फायदा उठा सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि, हम इस पर विचार कर सकते हैं और हमें कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, खासकर फील्डिंग पर। यह खेल का एक ऐसा पहलू है जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रशंसकों से मिले समर्थन पर उय्यर ने कहा कि जिस तरह से वे बड़ी संख्या में आए और हमारा समर्थन किया, उससे मैदान पर उतरते समय हमें बहुत आत्मविश्वास मिला। उनके प्यार और समर्थन का बहुत महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हर मैच में हमें ऐसा ही समर्थन मिलता रहेगा।

नई दिल्ली में फिटनेस का उत्साह, 'संडे ऑन साइकिल' में जुटे 1,000 प्रतिभागी

नई दिल्ली। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 97वें संस्करण का आयोजन रविवार को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस और ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की थीम 'एक सप्ताह, सात कदम, एक धरती' रखी गई।

कार्यक्रम में करीब 1,000 फिटनेस प्रेमियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन देशभर में एक साथ चलाए जा रहे फिट इंडिया के संडे ऑन साइकिल अभियान का हिस्सा रहा। दिसंबर 2024 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक देशभर के करीब 31,000 स्थानों पर लगभग 37 लाख लोग भागीदारी कर चुके हैं। यह आंकड़ा देश में फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता और लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल जाने-माने बॉडीबिल्डर दीपक शर्मा ने प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां फिटनेस का जोश और ऊर्जा देखने लायक है। युवाओं को इस पहल से जुड़ते देखना बेहद उत्साहजनक है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो साल से भी कम समय में देशभर के करीब 37 लाख लोगों का संडे ऑन साइकिल अभियान से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। फिटनेस ही वास्तविक संपत्ति है और हमें 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' के मंत्र को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में फिटनेस, खेल, योग, शिक्षा और साइकिलिंग से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस खिलाड़ी, फिटनेस कोच और प्रमाणित योग प्रशिक्षक ज्योति भारती तथा योग एवं मेडिटेशन कोच पंखुड़ी श्रीवास्तव शामिल रहीं।

कार्यक्रम की शुरुआत पंखुड़ी श्रीवास्तव के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत की शपथ के साथ हुई। इस दौरान प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद निर्धारित मार्ग पर 5 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई। सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई आकर्षक गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीता हांगकांग सिक्सेस का खिताब

हांगकांग। अफगानिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2026 टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड पर खेले गए फाइनल (कप) मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवरों में अफगानिस्तान के सामने 116 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अफगान टीम ने महज 5.1 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना खिताब जीता।

गुलबदीन नायब की कप्तानी में अफगानिस्तान हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीतने वाला आठवां देश बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित छह ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। टीम की ओर से मैक्स ब्रायंट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से 44 रन की पारी खेली। उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके अलावा एलेक्स रॉस ने नाबाद 29 रन और निक हॉब्सन ने 23 रनों का योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के सामने 116 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। अफगानिस्तान की ओर से करीम जनत और नांगेलिया खरोटे ने एक-एक विकेट हासिल किया। 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी



अफगानिस्तान की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। इमरान मीर ने 14 गेंदों में 2 चौके और साथ छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए। वहीं, फरमानुल्लाह सफी ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने सात गेंदों में चार छक्कों की मदद से नाबाद 26 रन बनाए। कप्तान गुलबदीन नायब ने भी जीत में अहम योगदान दिया और छह गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 17 रन बनाए।

अफगानिस्तान ने 5.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत लिया। इस तरह टीम ने पांच गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर पहली बार हांगकांग सिक्सेस की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कामयाबी पर खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन और अफगान क्रिकेट फैन्स को बधाई दी है। 'हांगकांग सिक्सस' एक अंतरराष्ट्रीय 'सिक्स-ए-साइड' (छह खिलाड़ियों वाली) क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो हर साल हांगकांग में आयोजित किया जाता है।

प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में वाराणसी का दबदबा

वाराणसी,एजेंसी। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरी उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में वाराणसी की टीम ने चार गुणे 100 मीटर और चार गुणे 400 मीटर रिले स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना दबदबा कायम किया।

उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता का समापन रविवार को सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एवं जिला एथलेटिक्स संघ, वाराणसी के सचिव रमेश कुमार यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इससे पहले क्षेत्रीय खेल कार्यालय के क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। त्रिकूद में चित्रकूट के लक्ष्मी प्रसाद ने प्रथम, बस्ती के सनी ने द्वितीय और आजमगढ़ के सचिन कन्नौजिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर दौड़ में वाराणसी के नीरज प्रथम और राहुल पाल द्वितीय रहे। 400 मीटर बाधा दौड़ में बरेली के अफरोज बाबू ने पहला, गोरखपुर के मोहम्मद



शाहिद ने दूसरा और अलीगढ़ के शिवम सिरोही ने तीसरा स्थान हासिल किया। ऊंची कूद में अयोध्या के कुनाल सिंह प्रथम, चित्रकूट के अतुल कुमार द्वितीय और अयोध्या के दिव्यांशु पांडेय तृतीय स्थान पर रहे। भाला फेंक स्पर्धा में लखनऊ के शिवा कुमार ने पहला, आजमगढ़ के सुमित कुमार ने दूसरा और बस्ती के रितेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, 200 मीटर दौड़ में चित्रकूट के शिवकुमार प्रथम, वाराणसी के अंकित पाल द्वितीय और आगरा के यश चौधरी तृतीय रहे। रिले स्पर्धाओं में वाराणसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चार गुणे 100 मीटर रिले में वाराणसी ने पहला, बरेली ने दूसरा और अयोध्या ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह चार गुणे 400 मीटर रिले में भी वाराणसी की टीम विजेता रही, जबकि बरेली दूसरे और बस्ती तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता की जानकारी वाराणसी मंडल के क्रीड़ा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का सफल संचालन कनाई चन्द्र तलापात्र ने किया।

दीपा मलिक ने 28वीं विश्व पैरा आर्मरिसलिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता एवं पद्मश्री सम्मानित दीपा मलिक ने रविवार को पूर्वी दिल्ली स्थित एक होटल में 28वीं विश्व पैरा आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 47वीं विश्व आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप के साथ आयोजित की जा रही है, जो 26 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगी। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुनिया के 60 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा पैरा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

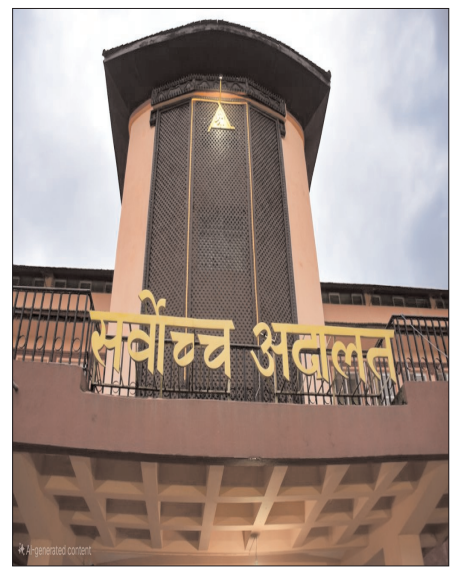
उद्घाटन समारोह में भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष और पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल के पूर्व शेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान भी मौजूद रहे। डॉ. दीपा मलिक वर्तमान में एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में दक्षिण एशिया की उप-क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह भारतीय पैरालंपिक समिति की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दीपा मलिक ने सभी खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने पीपुल्स आर्मरेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, एशियन आर्मरेसलिंग फेडरेशन की उपाध्यक्ष एवं प्रो पंजा लीग क सह संस्थापक प्रीति झंगियानी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रीति झंगियानी के माध्यम से उन्हें विश्व आर्मरेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष एसेन हाडजिटोदोरोव और महासचिव मिर्सिया सिमियोनेस्कु-सिमिसेल से जुड़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि खेल का असली उद्देश्य दोस्ती को बढ़ावा देना, बाधाओं को दूर करना और सीमाओं से आगे बढ़कर लोगों को एकजुट करना है। खेल हमें अलग-अलग संस्कृतियों को समझने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर देता है। यही सच्ची खेल भावना है।

दीपा मलिक ने कहा कि 60 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा पैरा खिलाड़ियों का भारत में एक साथ जुटना देश में समावेशी खेल व्यवस्था के विकास को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी के लिए समान अवसर और समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि जब भारत को बुल्गारिया में इन चैंपियनशिप की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब वह स्वयं वहां मौजूद थीं। अब इसे साकार होते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रीति झंगियानी और प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक परवीन डबास का आभार व्यक्त किया। दीपा मलिक ने कहा कि पैरा आर्मरेसलिंग बहुत ही लोकप्रिय खेल बनता जा रहा है। खुद एक एथलीट होने के नाते, यह मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की पल है। भारत में अभी त्योहारों का समय भी है और कुछ ही दिनों में हम दिवाली मनाएंगे इसलिए मेरी तरफ से सभी को त्योहारों की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि यह खेल आयोजन सभी के लिए बहुत शानदार रहे। सत्य प्रकाश सांगवान ने आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों का पहुंचना खुशी की बात है।

नेपाल में औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए तीन महीने में गांजे की नियंत्रित खेती की व्यवस्था करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गांजे की नियंत्रित व्यावसायिक खेती और उत्पादन की व्यवस्था करने का सरकार को आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति नहकुल सुवेदी और तिलप्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने मादक पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियमावली, मानक और कार्यविधि बनाने का सरकार को आदेश दिया है। अदालत ने परमादेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवश्यक कानूनी प्रावधान कर गांजे की नियंत्रित खेती और उत्पादन की व्यवस्था करने को कहा है। अधिवक्ता सरोज अधिकारी सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय को भी विपक्षी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी।इसी रिट पर 18 मई, 2025 को दिए गए फैसले का पूर्ण पाठ तैयार किया गया है। 9 सितंबर, 2025 को जेन-जी आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आगजनी के कारण मुकदमे की फाइलें जल गई थीं। इसी वजह से फैसले का पूर्ण पाठ तैयार करने में समय लगा।

अदालत के आदेश के अनुसार गांजे की व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, उपयोग, बिक्री-वितरण तथा निर्यात-आयात के लिए लाइसेंस और अनुमति देने की कानूनी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, बिना अनुमति गांजे की अवैध खेती, उत्पादन, निर्माण, तैयारी और बिक्री-वितरण जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कड़े नियमन और निगरानी तंत्र का निर्माण भी करना होगा। इससे पहले संघीय संसद में भी गांजे की व्यावसायिक खेती के लिए कानून बनाने के उद्देश्य से सांसदों ने एक गैर-सरकारी विधेयक पंजीकृत कराया था। हालांकि, वह विधेयक संसद में आगे नहीं बढ़ सका। सुप्रीम कोर्ट ने



कहा है कि मादक पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम जारी हुए करीब पांच दशक बीत जाने के बावजूद सरकार ने गांजे से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम या आदेश जारी नहीं किए हैं। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। अदालत के अनुसार कानून में निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के तहत गांजे की खेती, उत्पादन, बिक्री-वितरण और उपयोग की अनुमति दी गई है। लेकिन इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियमावली, कार्यविधि और मानक नहीं बनाए जाने के कारण कानून द्वारा दिए गए अवसरों का भी उपयोग नहीं हो सका है।

अधिनियम की धारा 4 के प्रतिबंधात्मक प्रावधान के अनुसार नेपाल के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले गांजे से चरस का उत्पादन, संग्रह और परिवहन करने के लिए नियम बनाकर लाइसेंस दिया जा सकता है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 5 में उपचार के लिए स्वीकृत चिकित्सक की सिफारिश पर लाइसेंस प्राप्त दुकान से मादक पदार्थ खरीदकर सेवन करने की व्यवस्था है। अदालत ने कहा कि कानून में निर्धारित वर्ग के लोगों को तय मात्रा में मादक पदार्थ सेवन करने की अनुमति देने का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 6 के तहत नेपाल सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कोई संस्था औषधि या वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से गांजे सहित अन्य मादक पदार्थों की खेती, तैयारी, उत्पादन, बिक्री-वितरण तथा निर्यात-आयात कर सकती है। हालांकि, इन कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 22 के अनुसार सरकार को नियम या आदेश जारी करना था।

अदालत का निष्कर्ष है कि कानून जारी होने के करीब 50 वर्ष बाद भी ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नियम नहीं बनाए जाने के कारण नेपाल अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण व्यवस्था द्वारा स्वीकार किए गए गांजे के औषधीय उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान से मिलने वाले संभावित लाभों का उपयोग नहीं कर सका है। अदालत ने लंबे समय तक कानून में निर्धारित प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने को सरकारी निकायों द्वारा अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति के रूप में व्याख्यायित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि गांजे से संबंधित नियम बनाते समय सरकार को केवल प्राकृतिक रूप से उगने वाले जंगली गांजे तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 के प्रतिबंधात्मक प्रावधान में पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले गांजे के संबंध में नियम बनाने की व्यवस्था है, जबकि धारा 6 औषधि और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए गांजे की खेती और उत्पादन की अनुमति देती है। अदालत ने अपने आदेश के आधार के रूप में अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था तथा गांजे पर हाल के अध्ययनों और अनुसंधानों को भी शामिल किया है।सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वर्ष 1961 के मादक पदार्थों पर एकल अभिसमय (सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1961) में नियंत्रित व्यवस्था के तहत गैर-औषधीय, बागवानी, कृषि तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गांजे की खेती की विशेष व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाल के विभिन्न अध्ययनों और अनुसंधानों ने गांजे के औषधीय महत्व को उजागर किया है। साथ ही, औद्योगिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में भी इसकी उपयोगिता सामने आई है। अदालत ने कहा कि नेपाल सरकार द्वारा स्वयं किए गए या कराए गए आधिकारिक अध्ययनों में भी औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गांजे की नियंत्रित खेती तथा उत्पादन की सिफारिश की गई है। इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने व्याख्या की है कि मादक पदार्थ (नियंत्रण) अधिनियम की भावना और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के विपरीत हुए बिना सरकार नियंत्रित प्रणाली के तहत गांजे की व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री-वितरण की व्यवस्था कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गांजे की नियंत्रित खेती की आवश्यक कानूनी व्यवस्था करने का आदेश दिया है, लेकिन मनोरंजन के लिए गांजे पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि गांजे के मनोरंजनात्मक उपयोग को कानूनी मान्यता देना या किसी गतिविधि को अपराध की सूची से हटाना व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

एक नजर

कतर के एलएनजी टैंकर पर हमले की सऊदी अरब और जीसीसी ने की निंदा

रियाद। खाड़ी क्षेत्र में कतर के एलएनजी टैंकर 'अल मयदा' को निशाना बनाए जाने की सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने कड़ी निंदा की है। दोनों ने इस घटना को समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि उसका देश कतर के साथ खड़ा है और अपने जहाजों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा के लिए कतर की ओर से उठाए जाने वाले सभी कदमों का समर्थन करता है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब समुद्री परिवहन की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी गतिविधि का विरोध करता है। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और समुद्री मार्गों व व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। वहीं, जीसीसी के महासचिव जसीम मोहम्मद अल-बुदैवी ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'खतरनाक तनावपूर्ण घटनाक्रम' बताया। उन्होंने कहा कि अरब की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अल-बुदैवी ने चेतावनी दी कि गैस टैंकरों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है, बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने हमले के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की। जीसीसी ने कतर के उन कदमों के प्रति समर्थन दोहराया, जिनका उद्देश्य उसके संसाधनों और संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा देश की सुरक्षा और हितों के लिए उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना है। 'अल मयदा' का स्वामित्व और संचालन कतर की गैस परिवहन कंपनी नकिलात के पास है। खाड़ी क्षेत्र में इस जहाज को पहले भी निशाना बनाया गया था।

नेपालः प्रधानमंत्री बालेन्द्र ने धमकीपूर्ण भाषा में किया फेसबुक पोस्ट



काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने चेतावनी दी है कि सही वक्त आने पर किसी को भी जवाबदेही से बचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शाह ने फेसबुक पर एक धमकीपूर्ण पोस्ट के जरिए यह टिप्पणी की। हालांकि, उन्होंने किसी विशेष घटना या व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा, 'सही वक्त आने पर सबका बुरा वक्त आएगा। किसी को यह सपना नहीं देखना चाहिए कि एक-दो लोग बच निकलेंगे। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी न्यायाधीशों के बिचौलियों के संपर्क में रहने की खबरों और मीडिया संस्थानों में पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर सरकार की आलोचना के बीच आई है। शाह की पोस्ट पर प्रधानमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार कुमार बेन ने भी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर 'सही वक्त' कब आएगा। रविवार दोपहर बेन ने सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट में 28 पत्रकारों को टैग किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या इस सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों को भी पत्रकार कहा जा सकता है।

ईरान को अमेरिका से कूटनीति को प्राथमिकता देने की उम्मीद : अराघची

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के साथ जारी शांति वार्ता को लेकर उम्मीद जताई है कि वाशिंगटन कूटनीति को दूसरे विकल्पों पर प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस दिशा में प्रयास कर रहा है और उसे उम्मीद है कि दूसरी तरफ भी समझदारी दिखाई जाएगी। अराघची ने कहा, 'हम इस दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ भी विवेकपूर्ण रुख अपनाया जाएगा तथा अन्य रास्तों के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ की ओर से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को जारी निर्देशों ने तेहरान के संकल्प को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सशस्त्र बलों को पिछले दो युद्धों के अनुभवों से काफी मजबूती मिली है और वे पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम हैं। अराघची के मुताबिक, सेना को अपनी जिम्मेदारियों और मिशन का स्पष्ट पता है।

यमन में मेडिकल कॉलेज पर हवाई हमले का आरोप, हूतियों ने सऊदी अरब को ठहराया जिम्मेदार

सना। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने होदेदा विश्वविद्यालय पर दो हवाई हमले होने का दावा किया है। हूती संचालित अल-मसीरा टीवी चैनल के अनुसार, हमलों में विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय को निशाना बनाया गया। संगठन ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सऊदी अरब की ओर से भी आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर होदेदा पिछले कई महीनों से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यहां हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज होने के बाद यमन में गृहयुद्ध ने फिर गंभीर रूप ले लिया है। इस संघर्ष के कारण देश पहले से ही लंबे समय से मानवीय संकट का सामना कर रहा है।

गाजा में इजराइली हमलों में 8 फिलिस्तीनियों की मौत, 5 पुलिसकर्मी भी शामिल

काहिरा। गाजा पट्टी में रविवार को इजराइल के दो अलग-अलग हवाई हमलों में कम-से-कम आठ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में पांच पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। चिकित्सा कर्मियों और हमास के नियंत्रण वाले गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। चिकित्सा कर्मियों के मुताबिक, गाजा सिटी में हुए इजराइली हवाई हमले में तीन लोगों की मौत हुई। वहीं, गृह मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी गाजा के पश्चिमी खान यूनिस इलाके में एक अन्य हमले में पांच पुलिस अधिकारी मारे गए। इजराइली सेना ने खान यूनिस में कई आतंकवादियों को निशाना बनाने की बात कही है। हालांकि, सेना ने इस कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। इजराइल का आरोप है कि हमास एक साल पुराने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए दोबारा हथियार जुटा रहा है और हमले कर रहा है। इसी के मद्देनजर इजराइल ने हाल के सप्ताहों में हमास के ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। दूसरी ओर, हमास ने हमले की तैयारी करने और अपने हथियारों का जखीरा दोबारा तैयार करने के आरोपों को खारिज किया है। संगठन का आरोप है कि इजराइल गाजा शांति समझौते को कमजोर कर रहा है।

बांग्लादेश में रिटायर्ड मेजर खंडाकर अब्दुल हाफिज गिरफ्तार



ढाका। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की जासूसी शाखा (डीबी) ने कथित राज्य विरोधी साजिश, हिंसक उकसावे, अवैध फंडिंग और सोशल मीडिया में प्रचार पर दर्ज मामले में मेजर (सेवानिवृत्त) खंडाकर अब्दुल हाफिज को गिरफ्तार किया है। जासूसी शाखा के अतिरिक्त आयुक्त एमडी शफीकुल इस्लाम ने कहा कि टीम ने गुरुवार देररात उसे राजधानी के बनानी इलाके से उठाया।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जासूसी शाखा के अतिरिक्त आयुक्त इस्लाम आज बताया कि हाफिज को उस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सेना के दो अन्य पूर्व अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। शफीकुल ने आरोप लगाया कि हाफिज, लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) देबाशीष कुमार बरुआ और लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) काजी गुलशन आरा राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। देबाशीष और गुलशन आरा आतंकवाद विरोधी कानून और साइबर सुरक्षा अध्यादेश की कई धाराओं के तहत पल्लबी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में फिलहाल जेल में हैं। इससे पहले डीबी ने 11 अक्टूबर की रात ढाका से दो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। पहले दावा किया गया था कि खंडाकर अब्दुल हाफिज को देश में अस्थिरता पैदा करने की कथित साजिश के तहत अवामी लीग की गतिविधियों से उनके कथित संबंधों के बारे में जानकारी थी, जिनकी गतिविधियों पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा हुआ है। डीबी ने कहा कि दोनों अधिकारियों को सोशल मीडिया पर राज्य विरोधी प्रचार में उनकी कथित संलिप्तता और साइबर अपराधों के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करने के प्रयासों के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

ईरान की होर्मुज को खोलने पर कतर से वार्ता, कहा-अमेरिका पहले शर्त माने

तेहरान (ईरान),एजेंसी। मध्य पूर्व में तनाव का प्रमुख कारण बन चुके होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने को लेकर कतर के मध्यस्थों के साथ ईरान के शीर्ष नेताओं की बातचीत चल रही है। ईरान ने कतर को साफ कर दिया है कि अमेरिका को पहले उसकी शर्तें मानने को तैयार होना होगा। ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका अगर शर्तें मान लेता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य को दो दिन में फिर से खोल दिया जाएगा। अल जजीरा और इरना की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कतरी मध्यस्थों के चल रही बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को दो दिन में फिर से खोलने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि अमेरिका को उनकी सभी मांगें माननी होंगी। उधर, ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पत्र को देखा है। इसके अध्ययन से साफ है कि वाशिंगटन के रुख में पूरी तरह से बदलाव आया है। उन्होंने इस बदलाव को एक सकारात्मक संकेत बताया है।

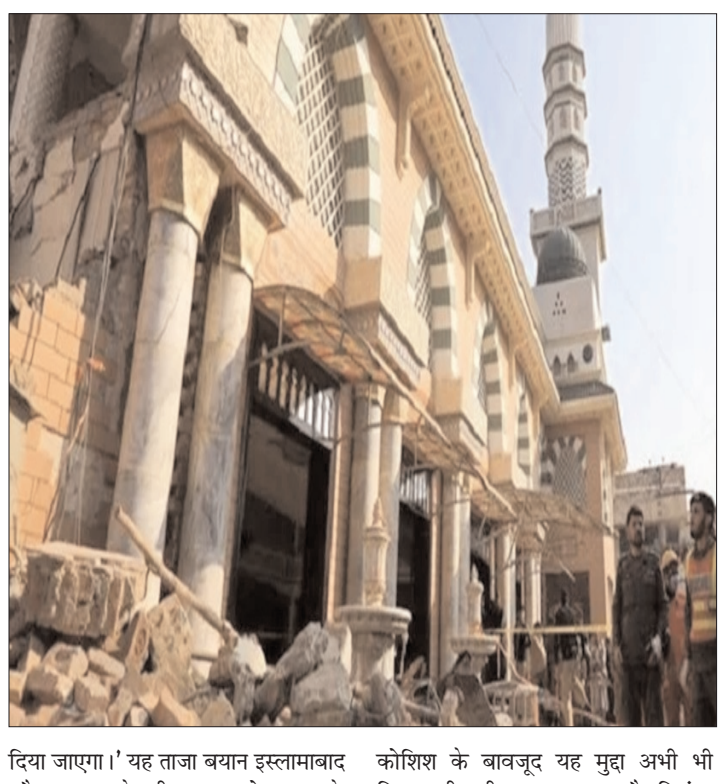
इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका और इजराइल की ओर से आने वाले किसी भी संभावित खतरे का 'बिना किसी भौगोलिक सीमा के, तत्काल और प्रभावी जवाब' दें। सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि खामेनेई के निर्देश के बाद ईरानी बल तैयार हैं।



मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने शनिवार को बताया कि कमांडर-इन-चीफ अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को दिए गए आदेश के बाद ईरानी सशस्त्र बलों ने अपने एजेंडे में दुश्मन के ठिकानों और संपत्तियों की एक नई सूची शामिल की है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक क्रांति के नेता का समझदारी भरा और निर्णायक नेतृत्व सशस्त्र बलों के कमांडरों और सभी सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। अब्दुल्लाही ने कहा कि सशस्त्र बल किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने कमांडर-इन-चीफ और देश को भरोसा दिलाया कि वे अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। शीर्ष कमांडर ने कहा कि ईरानी सेना आधुनिक और उन्नत उपकरणों व तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी भौगोलिक सीमा के पूरी ताकत और तीव्रता के साथ अमेरिकी और दुश्मनों का मुकाबला करेगी।

पाकिस्तान ने चेताया- 'आतंकवाद पर अफगानिस्तान की निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं'

इस्लामाबाद। संघीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार देररात काबुल कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तालिबान नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है। वह तनावपूर्ण संबंधों के असल कारण यानी अफगानिस्तान से चल रहे आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने के बजाय इस्लामाबाद की नीतियों को दोष दे रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी, ''आतंकवाद पर अफगानिस्तान की निष्क्रियता अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान का रुख एकदम साफ है। आतंकवाद अस्वीकार्य है। अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।इस्लामाबाद सीमा पार मौजूद उन आतंकवादी ठिकानों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं।पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है, चाहे ये खतरे कहीं से भी आ रहे हों। मंत्रालय ने कहा, ' इस स्थिति के लिए अफगान तालिबान शासन जिम्मेदार है।'' मंत्रालय ने काबुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान की सुरक्षा को अफगान तालिबान की निष्क्रियता, टालमटोल या गलत प्राथमिकताओं का बंधक नहीं बनने



दिया जाएगा।' यह ताजा बयान इस्लामाबाद और काबुल के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज' के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में पाकिस्तान में 225 आतंकी हमले हुए। पिछले 12 साल में किसी एक महीने में हुए हमलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। राजनयिक बातचीत और मध्यस्थता की कोशिश के बावजूद यह मुद्दा अभी भी विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है। सितंबर में, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल, इस्लामाबाद के साथ बातचीत और सहयोग जारी रखना चाहता है। वहीं, पाकिस्तान का कहना है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए चरमपंथी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है।

हमले का जवाब देने को तैयार ईरान का दावा, अमेरिकी युद्धपोत बच नहीं पाएंगे

तेहरान (ईरान)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नए हमले की चेतावनी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। ईरान के सबसे ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। तैयारी इस स्तर पर की गई है कि अगर अमेरिका लड़ाई में अपने युद्धपोत झोंकता है तो उन्हें समुद्र में दफन कर दिया जाएगा।

अल जजीरा की रिपोर्ट में 'फार्स' न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया है गया कि आईआरजीसी के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल यादुल्लाह जवनी के मुताबिक ईरानी सेना इस संभावना को ध्यान में रखकर काम कर रही है कि अमेरिका या इजराइल कभी भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'सेना दुश्मन की किसी भी चाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।' उन्होंने कहा कि ईरान को अचानक चौंकाया नहीं जा सकेगा और वह जरूरत के हिसाब से जवाब देगा। जवनी ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता पहले से सुदृढ़ हो गई है। हमले का अंदेशा होते ही जवाबी हमले शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों पर भारी और विनाशकारी हमला करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन की सेना हमारे किसी भी इलाके में घुसने की कोशिश करती है, वह क्षेत्र मौत का मैदान बन जाएगा। इस बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वह नए हथियारों



का इस्तेमाल करके हमलावर को करारा जवाब देगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए ईरान की सात शर्तों को पूरा करना जरूरी है। रेजाई ने कहा कि देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के आह्वान से सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ा है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना को काफी हद तक कमजोर किया जा चुका है। युद्ध रोकने के लिए बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका को आक्रामक कार्रवाई करने की जल्दी नहीं है। ट्रंप ने कहा, 'हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। अभी भी एक या दो ऐसी जगहें हैं, जहां हमला कर उन्हें नष्ट करना है।' उन्होंने एक संदिग्ध भूमिगत परमाणु परिसर का जिक्र करते हुए कहा, 'आप 'पिकएक्स माउंटेन' को देख सकते हैं। वहां हम जल्द हमला कर सकते हैं।' हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है कि वहां कोई परमाणु गतिविधि चल रही है।

एक नजर

बांग्लादेश में बस हादसा, राहगीर की मौत, जमात के 30 कार्यकर्ता घायल

ढाका (बांग्लादेश)। देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के खुलना अंतर्गत सतखीरा के पाटकेलगहाटा में हुए बस हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई और जमात-ए-इस्लामी के कम से कम 30 कार्यकर्ता घायल हो गए। बस में सवार ये कार्यकर्ता सड़क किनारे एक खाई में जा गिरे। यह हादसा शनिवार रात करीब 8:30 बजे खुलना-सतखीरा राजमार्ग के चाराबोतोला इलाके में हुआ। जमात कार्यकर्ता खुलना से 11 दलीय गठबंधन के रोड मार्च से लौट रहे थे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान 65 वर्षीय अब्दुल खालिक मोल्लाह के रूप में हुई है। वह पाटकेलगहाटा के काशियाडांगा गांव में रहते थे। उनके पड़ोसी रिपन मुल्ला ने बताया कि खुलना में रोड मार्च में शामिल होने के बाद जमात कार्यकर्ता बस से सतखीरा लौट रहे थे। जब अब्दुल खालिक चाराबोतोला चौराहे के पास सड़क पार कर रहे थे तभी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बस सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी। सतखीरा जमात के महासचिव अजीजुर रहमान ने कहा कि जब बस रोड मार्च से लौट रही थी, तो बुजुर्ग अचानक बस के सामने आ गए। उन्होंने कहा, 'उन्हें बचाने की कोशिश में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को ले जा रही बस सड़क से उतरकर किनारे की खाई में जा गिरी, जिससे कम से कम 30 कार्यकर्ता घायल हो गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति की भी मौत हो गई।' पटकेलघाटा पुलिस था प्रभारी तफजल हुसैन ने हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बस ड्राइवर की हालत गंभीर है, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

समाज को बांटने की सपा-कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी, 2027 में फिर 300 पार होगी भाजपा : केशव मौर्य

प्रयागराज। समाज को बांटने की सपा और कांग्रेस की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार 300 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वर्ष 2029 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी दलों की रैली पर कटाक्ष करते हुए यह बातें रविवार को प्रयागराज में मीडिया से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाजपा सरकार के अंगद का पैर होने संबंधी बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले 30 वर्षों तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।

दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन की रैली पर उन्होंने कहा कि रैली पूरी तरह असफल रही। इसे जनता का समर्थन नहीं मिला। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस बताए कि सरदार वल्लभभाई पटेल का वोट किसने चोरी किया था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसी तरह रायबरेली में राजनारायण की जीत के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें हरवाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न कभी वोट चोरी की है और न कभी करेगी। पार्टी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतती है और आगे भी जीतती रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मीडिया उन्हें दिखाना बंद कर दे तो वह दिखाई देना बंद हो जाएंगे। भाजपा के अंगद के पैर वाले बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी कि भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास जमीन नहीं है। भाजपा के पास वर्ष 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव परिणाम उदाहरण के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में भी हारने के बाद अखिलेश यादव वोट चोरी और ईवीएम खराब होने का आरोप लगाएंगे। लेकिन न वोट चोरी होगी और न ईवीएम धोखा देगी। जनता कमल का बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आजम खां की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जाने के मामले में केशव मौर्य ने कहा कि जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें हिंदू-मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। यदि विश्वविद्यालय बनाने में कोई अनियमितता हुई है और ईडी की जांच में सामने आई है तो कार्रवाई हुई है। आजम खां को लगता है कि ईडी ने गलत कार्रवाई की है तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए। इससे पूर्व बमरौली एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ल, राजेश गोंड, विक्रमजीत सिंह भदौरिया, अनुज कुशवाहा, आनंद सोनकर, मनोज कुशवाहा, विवेक मिश्रा और पवन श्रीवास्तव सहित पार्टी के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

अवैध घुसपैठ रोकना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, नाकाम रहने पर गृह मंत्री जवाबदेह : मदनी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समान नागरिक संहिता और मुसलमानों को निशाना बनाने के कथित प्रयासों के खिलाफ प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली,एजेंसी। जमीअत उलमा-ए-हिंद की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अवैध घुसपैठ, मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी विदेशी नागरिक की अवैध मौजूदगी का जमीअत समर्थन नहीं करती, लेकिन घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। हरियाणा के नूंह (मेवात) में 30 और 31 अक्टूबर को हुई इस बैठक में देशभर से 3,000 से अधिक उलमा ने हिस्सा लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि यदि गृह मंत्री अवैध घुसपैठ होने देते हैं या जानबूझकर इसे रोकने में नाकाम रहते हैं, तो वे सबसे बड़े गद्दार हैं। उन्होंने सवाल किया कि अवैध घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाले मंत्रालय से जवाब मांगने के बजाय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से निशाना क्यों बनाया जा रहा है।

जनसांख्यिकीय बदलावों पर स्वतंत्र आयोग की मांग

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुसलमानों की आबादी और जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर फैलाए जा रहे कथित भ्रामक नैरेटिव, विशेषकर 'डेमोग्राफिक जिहाद' के आरोपों को खारिज करते हुए प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 1981-1991 के दौरान 32.9 प्रतिशत थी, जो 2001-2011 में घटकर 24.7 प्रतिशत रह गई। जमीअत के अनुसार



जनसंख्या में बदलाव को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समझा जाना चाहिए, न कि सांप्रदायिक नजरिए से। संगठन ने मांग की कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को शामिल करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग गठित करे, जो प्रवासन, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करे।

बैठक में गुजरात, उत्तराखंड, असम और अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया।सामान नागरिक संहिताा को धार्मिक स्वतंत्रता, पारिवारिक मामलों में स्वायत्तता और संविधान से मिले मौलिक अधिकारों के लिए चुनौती बताया। जमीअत के अनुसार विवाह, तलाक और विरासत से जुड़े इस्लामी नियम कुरआन और हदीस पर आधारित हैं। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। जमीअत ने उत्तराखंड और गुजरात में अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से दी गई छूट और मुसलमानों को इसके दायरे में लाने पर भी आपत्ति जताई। संगठन ने इसे समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में विचारणीय बताते हुए अनुच्छेद 14, 25 और 26 का हवाला दिया। कार्यकारिणी ने सामान नागरिक संहिता के खिलाफ कानूनी लड़ाई को तेज करने और उत्तराखंड, गुजरात तथा असम के संबंधित कानूनों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर व्यापक लोकतांत्रिक अभियान चलाने का आह्वान किया।राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और संबंधित राज्यों के राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। मौलाना मदनी ने बहुसंख्यक समुदाय के खतरे में होने के राजनीतिक नैरेटिव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की असली चुनौती बहुसंख्यक समुदाय की सुरक्षा नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीतिक पदों की भूख है। उन्होंने मुसलमानों से शरीअत के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने के साथ परिवारों में महिलाओं के अधिकारों और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। विशेष रूप से तलाक, भरण-पोषण और मेहर से जुड़े मामलों को ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से निपटाने पर जोर दिया।

लोक सभा अध्यक्ष तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र पीएसी के सभापतियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन



नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को केरलम के तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों (पीएसी) के सभापतियों के एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के अनुसार दो दिवसीय सम्मेलन में 'लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं सुशासन -लोक लेखा समिति की उभरती भूमिका' विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में सार्वजनिक व्यय की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोक लेखा समितियों को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा होगी। सार्वजनिक व्यय की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने वाली कि जनधन का उपयोग विधायिका की मंशा एवं स्वीकृति के अनुरूप हो, लोक लेखा समितियां जवाबदेही और उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस सम्मेलन में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, लेखा परीक्षा के बदलते परिदृश्य तथा विधायी समीक्षा एवं निगरानी की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है। सम्मेलन का समापन बुधवार, चार नवंबर को होगा। इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केरलम विधान सभा के अध्यक्ष तथा संसद की लोक लेखा समिति के सभापति भी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केरलम विधान सभा की उपाध्यक्ष स्वागत भाषण देंगी, जबकि केरलम विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उद्घाटन सत्र में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, केरलम विधान सभा के अध्यक्ष थिरुवनचूर राधाकृष्णन तथा केरलम विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति के. एन. बालगोपाल उपस्थित रहेंगे।

समाजवादी पार्टी विकास बाधित करने और माफिया संस्कृति को प्रश्रय देने वाला दल : योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर को नगरीय जीवन सुगमता के लिए 880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 2017 से पहले की सपा पर विकास बाधित करने और माफिया संस्कृति को प्रश्रय देने के लिए निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। जब भी मौका मिला, जमीन कब्जा करना इन लोगों की प्रवृत्ति है।

मुख्यमंत्री योगी रविवार शाम 495.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण गोड़धोइया नाला परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण और 92.72 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 721.40 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए-3 और गोड़धोइया नाला के किनारे 65.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सपा शासन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जेल रोड पर गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की दो हवेलियां हुआ करती थीं। सपा सरकार के समय उस पर एक बार जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस समय विरोध किया गया और उस रईस परिवार ने सपा के माफिया से जमीन बचाने के लिए अपनी दोनों हवेलियों को रात्रि भर में गिरा दिया। मुख्यमंत्री ने एक अन्य घटना सुनाते हुए कहा, 'इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने एक प्रतिष्ठित परिवार के हवेली को कब्जा करने का प्रयास किया



तो बतौर सांसद मैं स्वयं मौके पर गया था। मैंने पब्लिक से वहां पर कहा था इन गुंडों को पकड़-पकड़ के मारो। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 के बाद कानून व्यवस्था में आए अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई किसी गरीब, व्यापारी या सम्मानित नागरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ऐसा करने से पहले वह दस बार सोचेगा।

कब्जा करने का मतलब उसको मालूम है कि अगले ही पल उसका क्या हिसाब होने वाला है। जबकि 2017 के पहले यह स्थिति नहीं थी। असुरक्षा का वातावरण था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार करने की स्थिति में नहीं था। कहीं भी सुरक्षा की स्थिति नहीं थी और जब सुरक्षा नहीं थी तो कोई निवेश भी नहीं करता था। जबकि आज गोरखपुर में किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जमीन या मकान पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई किसी युवा के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसी राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है। अगर किसी ने किया तो उसे जेल या जहन्नुम में से किसी एक रास्ते पर जाना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षा न दे सके, उसके लिए इससे ज्यादा नरकीय स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। इसीलिए सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार में अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आवागमन के माध्यम नहीं थे, गड्ढों में हमारे शहर की सड़कें खो चुकी थीं। एक बरसात आती थी तो गोरखपुर के अंदर भीषण जलजमाव होता था। जबकि आज गोरखपुर में जलजमाव नहीं है। आज से 10 वर्ष पहले गोरखपुर में चलने का मतलब केंचुए की चाल, रेंगते हुए चलना।

त्योहारी सीजन में सर्राफा बाजार में बड़ी गिरावट, 3,370 रुपये तक सस्ता हुआ सोना, चांदी भी 9,900 रुपये लुढ़का

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज जबरदस्त कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। सोना आज 3,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 3,370 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में आज लगातार 9,900 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह चांदी सिर्फ तीन दिन में ही लगभग 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है।

भाव में गिरावट आने के कारण देश के अलग अलग सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,38,880 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,27,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के कारण सोना और चांदी दोनों धातुओं के भाव में कमजोरी दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह के कारोबार में 24 कैरेट सोना 3,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया। इसी तरह 22 कैरेट सोना साप्ताहिक आधार पर 3,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। चांदी भी कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से पिछले सप्ताह के कारोबार में



लगातार गिरावट का सामना करता रहा। का भाव सप्ताहिक आधार पर 20,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गया।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,450 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,38,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,38,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,38,880 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,38,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,27,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,27,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,38,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोना 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

गुजरात भाजपा की बैठक में तरुण चुघ ने संगठन को मजबूत बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने पर दिया जोर

गांधीनगर। गुजरात भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुघ की विशेष उपस्थिति तथा प्रदेश अध्यक्ष जगदीशभाई विश्वकर्मा की अध्यक्षता में रविवार को गांधीनगर के कोबा स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय 'श्री कमलम' में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकरजी, प्रदेश सह-प्रभारी अजय महावर व गोमती साय , प्रदेश सह-संगठन महामंत्री अरुण बिन्नाड़ी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला एवं महानगर अध्यक्ष तथा प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान, जनजातीय गौरव अभियान सहित आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रदेश प्रभारी तरुण चुघ ने संगठन की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, मजबूत समन्वय तथा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संवाद और तालमेल के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने भाजपा की विकास और राष्ट्रवाद की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने तथा विपक्ष के दुष्प्रचार का



तथ्यों के आधार पर जवाब देने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में स्थानीय स्तर पर प्रभावी जनसंपर्क को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में उसके दुष्प्रचार के जवाब में सही जानकारी जनता तक पहुंचाना आवश्यक है।बैठक में प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रशांतभाई कोराट ने अभियान के तहत राज्यभर में आयोजित होने वाले युवा संवाद कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री अजयभाई ब्रह्मभट्ट ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के जोनवार आयोजन, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन और प्रभावशाली नागरिकों तक पहुंच बनाने से जुड़े कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया। प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष गणपतभाई वसावा ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव अभियान के तहत प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में स्वागत भाषण प्रदेश महामंत्री अनिरुद्धभाई दवे ने दिया, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री हितेंद्रसिंह चौहान ने किया।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)